04 - बड़बोलापन से नहीं बदलती तस्वीर

05 - बच्चे घर आ रहे हैं और जिंदगी धड़क उठी है

A Daily News Magazine
भोपाल
सोमवार, 17 नवम्बर, 2025

06 - अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर बैतूल में खुलकर हुई चर्चा...

07 - महिला उद्यमिता को नई उड़ान, महिलाओं को 'लखपति दीदी'

भोपाल एवं इंदौर से एक साथ प्रकाशित

वर्ष 23, अंक 77, नगर संस्करण, पृष्ठ 8, मूल्य रू. 2

प्रसंगवश

क्या अब बंगाल में ममता के क़िले को भेद पाएगी बीजेपी?

जुगल पुरोहित

बिहार विधानसभा चुनाव नतीजों के शुरुआती रुझान में राष्ट्री य जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को बढ़त दिखने लगी थी। इसी दौरान दोपहर 12 बजकर पाँच मिनट पर भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई ने एक्स पर पोस्ट किया। अब पश्चिम बंगाल। बिहार के नतीजे साफ़ होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा, गंगाजी, बिहार से बहते हुए ही बंगाल तक पहुँचती हैं। बिहार ने बंगाल में बीजेपी की विजय का रास्ता भी बना दिया है। अब बीजेपी पश्चिम बंगाल से भी जंगलराज को उखाड़ फेंकेगी।

ये टिप्पणियां राजनीतिक तौर पर अहम मानी जा रही हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं। भारत के इस पूर्वी राज्य में पिछला चुनाव 2021 की गर्मियों में कोविड-19 की दूसरी और बेहद ख़तरनाक लहर के बीच हुआ था। यहाँ विधानसभा की 294 सीटें हैं। ममता बनर्जी के नेतृत्व4 वाली तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने बीजेपी को शिकस्त दी थी। टीएमसी ने 215 सीटें जीती थीं। बीजेपी को 77 सीटें मिली थीं। टीएमसी को लगभग 48 फ़ीसदी वोट मिले थे और बीजेपी को 38 फ़ीसदी। ऐसे में राजनीतिक तौर पर इन दोनों राज्यों को कैसे देखा जाए? हालांकि टीएमसी ने भाजपा नेताओं के दावों को खारिज किया है। टीएमसी नेता कुणाल घोष ने एक पोस्टै में कहा, बंगाल की राजनीतिक किस्मत पटना या दिल्ली में नहीं लिखी जाती। यह यहाँ लिखी जाती है, उन लोगों द्वारा जिन्होंने बार-बार बीजेपी की बाँटने वाली राजनीति को नकारा है और ममता बनर्जी पर भरोसा जताया हैज साल 2026 में बीजेपी का वही अंजाम होगा, जो हमेशा बंगाल में होता आया है- नाकामी और अप्रासंगिकता।

बिहार में चुनाव से पहले गहन मतदाता पुनरीक्षण (एसआईआर) हुआ था। इस पर काफ़ी विवाद भी हुआ। बिहार में हार स्वीकार करते हुए भी, कांग्रेस के कुछ नेताओं ने एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान कथित तौर पर मतदाता सूची से लोगों के नाम हटाने की ओर इशारा किया। भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के अनुसार बिहार के बाद एसआईआर का दूसरा चरण नौ राज्यों और तीन केंद्र शासित प्रदेशों में चल रहा है। इसमें पश्चिम बंगाल भी शामिल है। कई विपक्षी पार्टियों ने बिहार की तरह ही इस चरण की प्रक्रिया पर भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस प्रक्रिया को पहले ही पीछे के दरवाज़े से एनआरसी लाने की 'चाल' बता चुकी हैं।

हिन्दुपस्तान टाइम्स की पॉलिटिकल एडिटर सुनेत्रा चौधरी कहती हैं कि अखिलेश यादव ने एनडीए की जीत का श्रेय एसआईआर को कहीं न कहीं दिया है। मुझे लगता है ममता भी यही करेंगी। वह शायद चुनाव आयोग के खिलाफ और ज़्यादा आक्रामक होंगी। ममता बहुत जल्दी सीखती हैं। बिहार में महागठबंधन के मुक़ाबले वह बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा संगठित और मज़बूत लड़ाई लड़ेंगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड की कंसल्टिंग एडिटर अदिति फडणीस मानती हैं कि यह कहना अभी जल्दबाज़ी होगी कि एसआईआर का पश्चिम बंगाल पर राजनीतिक या प्रशासनिक असर क्या होगा। वहां एसआईआर की प्रक्रिया 4 दिसंबर तक चलेगी। यह माना जा रहा है कि नीतीश कुमार ने महिला मतदाताओं को अपनी मुख्य ताक़त के रूप में जोड़ने की कामयाब कोशिश की है। इस चुनाव में महिला मतदाताओं की भागीदारी पुरुषों से अधिक रही।

भारत में मुख्य मंत्री काफ़ी कम महिलाएँ हुई हैं। ममता बनर्जी इनमें से एक हैं। उन्हें भी अक्सर महिला मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का श्रेय दिया जाता है। उनकी सरकार ने कई योजनाएँ शुरू कीं। इनमें से कुछ सीधे महिलाओं और लड़कियों के लिए हैं, जैसे, लड़कियों को पढ़ाई जारी रखने के लिए आर्थियक मदद और ग्रामीण इलाक़ों में ग़रीब परिवारों की महिलाओं को संगठित करके रोज़गार के जरिए उनकी क्षमता बढ़ाना। हालाँकि, हाल के समय में राज्य में महिलाओं के साथ यौन हिंसा की कई घटनाएँ हुईं। बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हुए। इसके बाद यह सवाल भी उठ रहा है कि क्या अब भी उनकी इस महिला वर्ग पर उतनी ही मज़बूत पकड़ है?

बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों राज्यों की सीमाएँ पड़ोसी देशों से लगती हैं। बिहार की नेपाल से और पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश और नेपाल से। ये सीमाएँ कई जगह खुली हैं और यहाँ से विदेशी नागरिकों के अनियंत्रित प्रवेश के आरोप समय-समय पर लगते रहे हैं। दोनों राज्यों की प्रति व्यक्ति सालाना आय राष्ट्रीय औसत से कम है। लेकिन कई मामलों में दोनों अलग भी हैं। नीति आयोग के मुताबिक़, पश्चिम बंगाल की मौजूदा प्रति व्यक्ति सालाना औसत आय 1,54 हजार रुपए से अधिक है। यह बिहार के 60,337 रुपए से दोगुनी है।

मतदाताओं की संख्या में भी अंतर है। बिहार में एसआईआर के बाद 7.4 करोड़ से ज़्यादा मतदाता हैं, जबकि चुनाव आयोग के अनुसार पश्चिम बंगाल में अक्तूबर 2025 तक 7.6 करोड़ से अधिक मतदाता थे। अदिति फडणीस बताती हैं, मैं इन दोनों राज्यों को बिल्कुल अलग मानती हूँ। बिहार में बीजेपी सरकार में थी और क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ उसकी मज़बूत मौजूदगी थी। पश्चिम बंगाल में ऐसा नहीं है। साथ ही, बिहार में नीतीश कुमार की मौजूदगी से एनडीए को मुस्लिम वोट भी मिला होगा, जो शायद पश्चिम बंगाल में संभव न हो क्योंकि वहाँ लड़ाई ज़्यादा ध्रुवीकृत होगी।

कोलकाता के विश्लेषक सुदीप्त सेनगुप्ता के अनुसार बीजेपी ने बिहार में जीत हासिल की है, लेकिन इससे पश्चिम बंगाल की ज़मीनी हक़ीक़त बिहार से बिल्कुल अलग है। पश्चिम बंगाल में एक मज़बूत पार्टी सत्ता में है। आजकल राज्य के चुनाव नेता के चेहरे पर केंद्रित होते हैं। बीजेपी के मुक़ाबले, यह बात टीएमसी को फ़ायदा देती है। ममता बनर्जी की उम्मीदवारी के बारे में कोई शक नहीं है, जबकि बीजेपी के पास अभी ऐसा चेहरा नहीं है। दूसरी ओर, बीजेपी विपक्ष में रहते हुए भी अपनी रणनीति मज़बूती से नहीं बना पाई है। इस सवाल के जवाब में कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी किस क़िस्म की रणनीति अपनाएगी? तो उन्होंने कहा कि बीजेपी की रणनीति हिंदुत्व पर केंद्रित है। पश्चिम बंगाल में यह सबसे बड़ा वोट पाने वाला मुद्दा नहीं रहा है। अब बीजेपी मतुआ समुदाय पर ध्यान दे रही है। जो पूर्वी पाकिस्तान (अब बांग्लादेश) से आए शरणार्थियों का समूह है। पार्टी जाति के आधार पर यह तर्क दे रही है कि राज्य में हमेशा ऊँची जाति के लोग हावी रहे हैं। वह एक तथाकथित पिछड़े वर्ग के उम्मीदवार को आगे लाने का प्रयास करेगी। लेकिन देखना होगा कि इस तरह के अभियान को कितनी कामयाबी मिलती है।

(बीबीसी हिंदी में प्रकाशित लेख के संपादित अंश)

subahsaverenews@gmail.com
facebook.com/subahsaverenews
www.subahsavere.news
twitter.com/subahsaverenews

शरद की सुबह

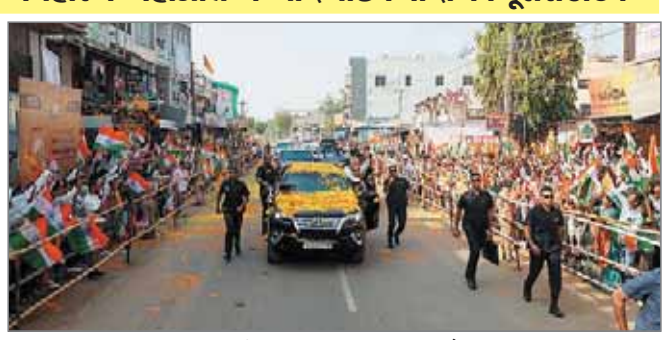

आँधी आई जोर शोर से,
डालें टूटी हैं झकोर से।
उड़ा घोंसला अंडे फूटे,
किससे दुख की बात कहेगी!
अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी?
हमने खोला आलमारी को,
बुला रहे हैं बेचारी को।
पर वो चीं–चीं कर्राती है
घर में तो वो नहीं रहेगी!
घर में पेड़ कहाँ से लाएँ,
कैसे यह घोंसला बनाएँ!
कैसे फूटे अंडे जोड़े,
किससे यह सब बात कहेगी!
अब यह चिड़िया कहाँ रहेगी?

– महादेवी वर्मा

संसद में कांग्रेस युवा सांसदों को बोलने तक नहीं देती है

बिहार में 'महाजीत' के बाद पीएम मोदी का दूसरा अटैक

अहमदाबाद/सूरत (एजेंसी)। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में जेडीयू-बीजेपी की बड़ी जीत के बाद कांग्रेस पर दूसरा अटैक किया है। पीएम मोदी ने गुजरात के सूरत में एक कार्यक्रम में कहा कि संसद में कांग्रेस अपने युवा सांसदों को बोलने तक नहीं देती है। उनका करियर खत्म हो रहा है। पीएम मोदी ने इससे पहले कहा था कि कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। उन्होंने विभाजन की आशंका भी व्यक्त की थी। अब उन्होंने पार्टी की अंतर्कलह को लेकर निशाना साधा है। अगले महीने शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस में युवा सांसदों को बोलने का अवसर नहीं दिया जाता है। यह बात कई युवा सांसदों ने खुद उन्हें बताई है। प्रधानमंत्री मोदी ने सूरत में एक जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस का पूरा युवा वर्ग, जो पहली बार संसद आया है, वह अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। जब कांग्रेस और इंडी अलायंस के युवा सांसद मिलते हैं तो वे कहते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। हमारा करियर खत्म हो रहा है। हमें संसद में बोलने का मौका भी नहीं मिलता। हर बार यही कहा जाता है कि संसद को ताला लगा दो। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे युवा सांसद अपने क्षेत्रों में जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वे कहते हैं कि जब अपने क्षेत्रों के विषय को संसद में नहीं उठा पाएंगे तो दोबारा कौन मौका देगा। ऐसे में हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। हमें विकास की नई ऊंचाइयों को पार करना है। सीपीआई (एम) के राज्यसभा सदस्य जॉन ब्रिटास ने भी संसद के अंदर की स्थिति को लेकर खुलासा किया था।

चंद्रयान मिशन-4 को मंजूरी, साल 2027 में होगी लॉन्चिंग

● 2035 तक खुद का होगा अंतरिक्ष स्टेशन, इसरो की तैयारी

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत अंतरिक्ष में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, इस सफलता के पीछे इसरो के तमाम वैज्ञानिकों हाथ है। इसरो अब दुनिया को एक बार फिर अपनी ताकत दिखाने के लिए तैयार, इस वित्तीय वर्ष में 7 और लॉन्चिंग की जाएंगी। साथ ही भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान 2027 तक भेजे जाने की योजना पर भी काम चल रहा है। इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने एक इंटरव्यू में यह भी बताया कि इसरो अंतरिक्षयान उत्पादन क्षमता को तीन गुणा तक बढ़ाएगा। इंटरव्यू में इसरो के अध्यक्ष वी. नारायणन ने बताया कि इसरो तेजी से विस्तार के दौर से गुजर रहा है।

● **2035 तक होगा भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन–** नारायणन ने यह भी बताया कि इसरो 2035 तक अपना भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाने पर काम कर रहा है। इसके पांच मॉड्यूल में से पहला 2028 तक कक्षा में स्थापित कर दिया जाएगा। इससे भारत तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास अपना अंतरिक्ष स्टेशन होगा, क्योंकि अमेरिका के नेतृत्व वाला मिशन अपने अंत के करीब है और चीन का तियांगोंग पूरी तरह से चालू हो रहा है। भारत के पहले मानव–अंतरिक्ष उड़ान मिशन गगनयान को लेकर नारायणन ने स्पष्ट जानकारी दी।

मक्सी अब ग्रीन मैनूफैक्चरिंग हब के रूप में जाना जाएगा : मुख्यमंत्री

उज्जैन-शाजापुर की भूमि पर बनेंगे हरित ऊर्जा उपकरण

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि मालवा क्षेत्र, जो अपनी मीठी संस्कृति और उर्वर भूमि के लिए मशहूर है, अब ग्रीन एनर्जी का हब बनने जा रहा है। यह क्षेत्र विकास के नए संकल्पों के साथ नई ऊर्जा और उमंग से प्रदीप्त हो रहा है। शाजापुर जो सोने और नमकीन के लिए जाना जाता है, अब अपनी औद्योगिक प्रगति के लिए भी पहचाना जा रहा है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बाबा महाकाल की कृपा से उज्जैन-शाजापुर की पुण्यधरा हरित ऊर्जा उत्पादन में उपयोग होने वाले सभी उपकरणों का प्रोडक्शन सेंटर बनने जा रही है। उन्होंने कहा कि मक्सी नगर अब सेंट्रल इंडिया के ग्रीन मैनुफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित होकर अपनी नई पहचान कायम करेगा। इससे यहां के किसानों को अपने ही क्षेत्र में प्रोसेसिंग, पैकेजिंग और भंडारण की भी सुविधा मिलेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव रविवार को शाजापुर जिले के औद्योगिक प्रक्षेत्र मक्सी के दशहरा मैदान में विभिन्न औद्योगिक इकाइयों के भूमिपूजन एवं लोकार्पण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मक्सी नगर में करीब 8174 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली 6 औद्योगिक इकाइयों का भूमिपूजन एवं लोकार्पण किया। इसमें चार इकाइयों का भूमिपूजन एवं दो इकाइयों का लोकार्पण शामिल है। मुख्यमंत्री ने करीब 384 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से उज्जैन से मक्सी तक निर्मित होने वाली करीब 38.95 किलोमीटर लम्बी फोर लेन रोड़ निर्माण कार्य का भूमिपूजन भी किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में अपनी पावन परम्पराओं की चमक, प्रगति एवं समृद्धि की नई रौशनी और विकसित भविष्य की आहट सुनाई दे रही है। हम प्रदेश के युवाओं के सपनों में विकास के नए रंग भर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन सरकार की सरकार में हमारा मध्यप्रदेश समृद्धि और प्रगति की अनवरत यात्रा पर अग्रसर है। आज मक्सी औद्योगिक क्षेत्र में हुआ विभिन्न नवीन औद्योगिक इकाइयों के भूमिपूजन की एक-एक ईंट मालवा क्षेत्र की नई ऊर्जा और विकास का आधार बनेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि बहुतजल्द यह भूमि न केवल आध्यात्मिक प्रकाश में आलोकित होगी, बल्कि औद्योगिक ऊर्जा से भी दमकेगी। पार्वती-कालीसिंध नदी जोड़ो लिंक परियोजना का लाभ भी क्षेत्र को मिलेगा। आज मक्सी की इस ऊर्वर भूमि पर विकास का जो बीज बोया जा रहा है, वह आने वाले वर्षों में हजारों युवाओं के जीवन में समृद्धि लेकर आएगा। उन्होंने कहा कि आज शाजापुर जिले को डबल गिफ्ट मिल रहा है। औद्योगिक इकाइयों की स्थापना के साथ शाजापुर को कई विकास कार्यों की सौगातें भी दी जा रही हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आज यहां 487 करोड़ 36 लाख रुपये की लागत से 20 विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमिपूजन सम्पन्न हुआ है। छह औद्योगिक इकाइयों के भूमिपूजन और लोकार्पण से यहां 8174 करोड़ रुपये से अधिक का पूंजी निवेश आएगा। इससे इस क्षेत्र के 15 हज़ार से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश शांति, समरसता, सुशासन, औद्योगीकरण के साथ-साथ लोकतांत्रिक परम्पराओं के सहज स्थापन का केंद्र बन चुका है। हमारे यहां सब मिलकर साल भर होली-दीवाली मनाते हैं। हमारी बहनें हर महीने भाईदूज और रक्षाबंधन मनाती हैं। उन्होंने कहा कि जैसी नीयत, वैसी बरकत। बहनों के आर्थिक कल्याण के लिए हमने जो कहा वह किया। जो वादा किया था, वह पूरा करके भी दिखा दिया है। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहना योजना के तहत 1500 रुपए की मासिक आर्थिक सहायता के अलावा हमारी सरकार रोजगार आधारित उद्योगों में रोजगार पाने वाली कामकाजी बहनों को हर महीने 5 हजार रुपए की अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि देगी। उनके नियोक्ता की तरफ से जो मासिक वेतन मिलेगा, सो अलग।

बिहार चुनाव के बाद बढ़ने लगी माया-ओवैसी की नजदीकी

यूपी 2027 टारगेट के लिए बसपा-एआईएमआईएम की होगी जुगलबंदी

लखनऊ (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव में भले ही एनडीए गठबंधन ने बहुमत हासिल कर सरकार बनाने जा रही है, लेकिन इस चुनाव में हाथी के दांव ने बड़ी-बड़ी राजनीतिक दलों को हैरान कर दिया है। बसपा ने बिहार में एक सीट पर जीत दर्ज की है। वो भी तब जब बसपा दूर-दूर तक फाइट में नहीं थी। इतना ही नहीं, बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी सिर्फ एक-दो रैली ही की थी। ऐसे में बसपा में परफॉर्मेंस ने सभी को ना केवल चौंका दिया है, बल्कि यूपी चुनाव में बीजेपी और सपा के लिए मायावती सबसे बड़ा खतरा बन गई है। उधर असदुद्दीन ओवैसी के साथ अंदर खाने बसपा की बढ़ती नजदीकियां नई इबारत को लिखने की सुगबुगाहट को हवा दे रही है। दरअसल भले ही बहुजन समाज पार्टी ने बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ा है, लेकिन एआईएमआईएम नेताओं का बीएसपी के पक्ष में वोट करने के लिए कहना एक बड़ा संदेश दे रहा है। जानकारों की माने तो बसपा नेता अनिल पटेल और जीते कैंडीडेट पिंटू यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में ओवैसी की पार्टी का झंडा लगा था। इतना ही नहीं, पिंटू यादव की जीत के जुलूस में भी ओवैसी का झंडा दिख रहा था। इसके अलावा कई सीट पर पार्टी के उम्मीदवार आगे रहे।

● **असदुद्दीन ओवैसी और मायावती के बीच बातचीत–** इतना ही नहीं, गठबंधन होने के बावजूद असदुद्दीन ओवैसी ने चंद्रशेखर आजाद के साथ पूरे चुनाव में कही भी मंच नहीं साझा किया। ऐसा माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं असदुद्दीन ओवैसी और मायावती के बीच बातचीत जरूर हुई है। उसके बाद ही यह सब देखने को मिल रहा है। इसको लेकर वरिष्ठ पत्रकार ने सैयद कासिम ने बताते हैं कि मायावती बहुत साफ बोलती है। उन्हें समर्थन नहीं चाहिए होता तो वो साफ मना कर देती। मायावती अक्सर मंच से ही बिना नाम लिए सब कुछ कह देती है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला।

बसपा और एआईएमआईएम का यूपी में पुराना है नाता

बसपा सुप्रीमो मायावती मुस्लिम वोट के लिए असदुद्दीन ओवैसी के साथ जा सकती है। उधर, ओवैसी भी अपने ऊपर लगे धर्म विशेष के ठप्पे से निजात पाने के लिए मायावती के साथ जा सकते हैं। मायावती और ओवैसी 2020 बिहार चुनाव में पहले भी एक साथ गठबंधन में थे। बसपा एकलौती राष्ट्रीय पार्टी है, जिसने ओवैसी की पार्टी से गठबंधन किया है। वरिष्ठ पत्रकार ने कहा कि कुछ तो जरूर चल रहा है, जो मार्च–अप्रैल तक बड़े घटनाक्रम के तौर देखने को मिल सकता है। उस बड़े घटनाक्रम में ओवैसी का मायावती के साथ जाना भी हो सकता है। सैयद कासिम ने बताया कि बसपा और ओवैसी पर बीजेपी की बी टीम होने का आरोप वही पार्टियां लगाती है जो मुस्लिम वोट पाती है।

भोपाल का तापमान

अधिकतम 27 °c

न्यूनतम 23°c

सुबह सवेरे

भोपाल ■ सोमवार, 17 नवंबर 2025

जो अग्नि हमें गर्मी देती है , हमें नष्ट भी कर सकती है ; यह अग्नि का दोष नहीं है।

चाणक्य नीति

एसआईआर ने किया 'कमाल', अब ईसी करेगा 'धमाल'

● बिहार में एसआईआर के बाद अबकी जमकर हुआ मतदान

नई दिल्ली (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में मतदाताओं की अब तक की सबसे अधिक उपस्थिति दर्ज की गई। खासकर दो दशकों में पहली बार राज्य में एसआईआर के बाद भारी मतदान ने निर्वाचन आयोग के आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। आयोग अगले चरण में एक दर्जन अन्य राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर को लागू करने वाला है, जिनमें अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले राज्य भी शामिल हैं। मतदाताओं की भारी भागीदारी विपक्ष के वोट चोरी वाले आरोपों को कमजोर करती है। कांग्रेस के नेतृत्व में यह अभियान चलाया गया और राहुल गांधी ने राज्य में वोट अधिकार यात्रा भी निकाली। जनता के बीच इसे कोई खास समर्थन नहीं मिला। कांग्रेस के उम्मीदवार केवल 6 सीटों पर जीत पाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी विपक्षी दलों और कार्यकर्ताओं की याचिकाओं को खारिज कर दिया था, जिनमें बिहार में एसआईआर को रोकने या रद्द करने की मांग की गई थी। उन्हें डर था कि इससे कमजोर वर्गों और अल्पसंख्यकों के मतदाताओं का मताधिकार छीन लिया जाएगा।

इजरायल की तरह हमला करो, नहीं टिक पाएगा पाकिस्तान

● बलूच नेता का भारत को बड़ा ऑफर बताई मुनीर सेना की कमजोर नस

इस्लामाबाद (एजेंसी)। पाकिस्तान एक बार फिर भारत में 1990 के दशक जैसी हिंसा की परिस्थितियां बनाने की तैयारी कर रहा है। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के पास बम विस्फोट मामले की जांच में एजेंसियों को पाकिस्तान के आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के लिंक मिले हैं। मामले में हुई कई गिरफ्तारियों में पकड़े गए संदिग्धों के पाकिस्तानी हैंडलर्स से संपर्क की जानकारी सामने आई है। यह इस बात का संकेत है कि पाकिस्तान बड़ी योजना पर काम कर रहा है। इस बीच बलूचिस्तान के रक्षा विश्लेषकों ने भारत से अब सीधी कार्रवाई की मांग की है। बलूचिस्तान के अधिकार समूह के कार्यकर्ता मीर यार बलूच ने कहा कि पाकिस्तान का आतंकवाद छोड़ने का कोई इरादा नहीं है और कहा कि भारत को इजरायल की तरह बड़े पैमाने पर निर्णायक कार्रवाई पर विचार करना चाहिए। बलूच कार्यकर्ता ने कहा कि पाकिस्तान भारत एक महीने तक भी भारत के हमले नहीं झेल पाएगा। इसलिए भारत के लिए जरूरी है कि वह पाकिस्तान के आतंकी हमलों से शुरू हुए संघर्ष को निर्णायक रूप से खत्म करे। मीर यार बलूच ने कहा कि भारत को बलूचिस्तान और अफगानिस्तान में आपातकालीन ठिकानों पर खुले तौर पर रक्षात्मक और सैन्य सहायता देनी चाहिए।

सीमापार से जुड़े दिल्ली कार विस्फोट के तार!

● जैश ने डॉक्टर्स की टेरर टीम को भेजी थी रकम ● मनी ट्रेल का खुलासा

नई दिल्ली (एजेंसी)। दिल्ली में लाल किले के बाहर कार विस्फोट मामले में खुफिया एजेंसियों को एक बड़ी सफलता मिली है। खुफिया एजेंसियों ने तीन डॉक्टरों, उमर, मुजम्मिल और शाहीन से जुड़े 20 लाख रुपये के मनी ट्रेल का खुलासा किया है। सूत्रों ने रविवार को बताया कि यह रकम जैश-ए-मोहम्मद के एक हैंडलर द्वारा हवाला नेटवर्क के जरिये भेजी गई होने का शक है। ऐसा माना जा रहा है कि इस रकम में से करीब 3 लाख रुपये 26 क्विंटल एनपीके उर्वरक खरीदने पर खर्च किए गए, जो खेतीबाड़ी में इस्तेमाल होने वाला नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम बेस्ड केमिकल मिश्रण है, जिससे विस्फोट में इस्तेमाल होने वाले विस्फोटक भी बनाए जा सकते हैं। अधिकारियों ने आगे बताया कि पैसों को लेकर डॉ. उमर और डॉ. शाहीन के बीच कथित तौर पर मनमुटाव हो गया था।

सुप्रीम कोर्ट से खफा पशु-प्रेमी का प्रदर्शन

एक ही समय पर देशभर में इकट्ठे हुए लोग, भोपाल के शाहपुरा पार्क में जुटे

भोपाल (नप्र)। सुप्रीम कोर्ट द्वारा आवारा कुत्तों को स्कूल, कॉलेज, अस्पताल और बस स्टैंड जैसे संस्थागत क्षेत्रों से हटाने तथा उन्हें शेल्टर में रखने के आदेश के खिलाफ आज देशभर में एक साथ शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में भोपाल में भी रविवार को शाम 4 बजे बाद ऋषभदेव पार्क में पशु-अधिकार कार्यकर्ता और पशु-प्रेमी एकत्रित हुए।

इस बात की जानकारी देते हुए पीएफए की स्टेट प्रेसीडेंट स्वाति गौरव ने बताया कि राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे इस प्रदर्शन में विभिन्न शहरों के एनिमल एक्टिविस्ट, वॉलंटियर्स, रेस्क्यू ग्रुप्स और समाजसेवी संगठन शामिल हैं।

स्वाति का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश न केवल मौजूदा पशु क्रूरता निवारण कानून के खिलाफ है, बल्कि सामुदायिक कुत्तों के अधिकारों और सह-अस्तित्व की भावना पर भी आघात करता है।

एक्टिविस्ट्स का कहना है कि देश में लाखों सामुदायिक कुत्ते हैं और उन्हें हटाने का निर्णय न मानवतावादी दृष्टि से सही है और न ही व्यावहारिक। उनका मानना है कि यह आदेश उस वैज्ञानिक और कानूनी प्रक्रिया से भी विपरीत है, जिसमें कैप्चर-नसबंदी-टीकाकरण को ही सबसे प्रभावी तरीका माना गया है। स्वाति ने बताया कि आज का प्रदर्शन एक राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक है। प्रदर्शन का उद्देश्य सुप्रीम कोर्ट और सरकार दोनों का ध्यान इस ओर आकर्षित करना है कि कुत्तों को हटाने के बजाय नसबंदी, वैक्सीनेशन, समुदायिक देखभाल और कानून-आधारित समाधान पर जोर दिया जाए।

सुप्रीम कोर्ट का आदेश - आवारा कुत्तों और पशुओं पर सख्ती- सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि स्कूल, कॉलेज, अस्पताल, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों और पशुओं को हटाया जाए। कोर्ट ने कहा कि पकड़े गए कुत्तों को दोबारा उसी जगह नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि उन्हें शेल्टर होम में रखा जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने यह मामला 28 जुलाई को खुद संज्ञान में लिया था, जब एक मीडिया रिपोर्ट में दिल्ली में बच्चों को कुत्तों के काटने और रैबीज के मामलों का जिक्र था। अब कोर्ट ने इसका दायरा पूरे देश तक बढ़ा दिया है। अगली सुनवाई 13 जनवरी 2025 को होगी।

आसियान देशों का उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल 18 से 20 नवंबर तक भोपाल में

- राज्यपाल और मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात
- निवेश संगोष्ठी और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में होंगे शामिल

भोपाल (नप्र)। आसियान देशों के उच्च स्तरीय राजनयिकों का प्रतिनिधिमंडल 18 से 20 नवंबर तक तीन दिवसीय भोपाल प्रवास के दौरान कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे। इस भ्रमण का उद्देश्य मध्यप्रदेश और आसियान देशों के बीच आर्थिक, औद्योगिक, निवेश और सांस्कृतिक सहयोग को सुदृढ़ बनाना है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव से भेंट में औद्योगिक सहयोग पर चर्चा- मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से प्रतिनिधिमंडल 18 नवंबर को भेंट करेंगा। बैठक राज्य सरकार के निवेश-अनुकूल वातावरण, औद्योगिक नीति और आसियान देशों के साथ साझेदारी को लेकर केंद्रित रहेगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव प्रदेश में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक परिदृश्य, आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, एग्री-प्रोसेसिंग, पर्यटन और नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे। प्रतिनिधिमंडल प्रदेश सरकार द्वारा आयोजित रात्रिभोज में शामिल होगा। जिसमें दोनों पक्षों के बीच आपसी सहयोग और आर्थिक संबंधों को सुदृढ़ करने पर चर्चा भी होगी।

राज्यपाल से शिष्टाचार भेंट और निवेश संगोष्ठी में सहभागिता- राज्यपाल श्री मांगूभाई पटेल से प्रतिनिधिमंडल 19 नवंबर को शिष्टाचार भेंट करेगा। इसके बाद होटल कोर्टयार्ड मैरियट में ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट सेमिनार में शिरकत करेंगे। सेमिनार में राज्य के उद्योगपति, चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधि और प्रमुख निवेशक शामिल होंगे। इसमें मध्यप्रदेश के औद्योगिक विकास, इन्फ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक नेटवर्क और निवेश-अनुकूल नीतियों की प्रस्तुति दी जाएगी।

मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक समृद्धि से होंगे रूबरू- प्रतिनिधिमंडल अपने भ्रमण के दूसरे दिन 19 नवंबर को साँची और भीमबेटका जैसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल विश्व प्रसिद्ध स्थलों का भ्रमण करेगा। इससे उन्हें मध्यप्रदेश की प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा, बौद्ध कला और ऐतिहासिक धरोहरों से परिचित होने का अवसर मिलेगा। भ्रमण के तीसरे दिन 20 नवंबर को प्रतिनिधिमंडल भोपाल स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय और जनजातीय संग्रहालय का भी अवलोकन करेगा।

राज्य सरकार का यह प्रयास प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के 'एक्ट ईस्ट पॉलिसी' के अनुरूप है, जिसके माध्यम से भारत और दक्षिण-पूर्व एशिया के बीच आर्थिक, निवेश और सांस्कृतिक संबंधों को और मजबूत किया जा रहा है। मध्यप्रदेश, अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति, मजबूत औद्योगिक आधार, निवेश-अनुकूल नीतियों और तेजी से विकसित होते बुनियादी ढांचे से आसियान देशों के लिए आकर्षक निवेश गंतव्य बनकर उभर रहा है।

यह दौरा मध्यप्रदेश और आसियान देशों के बीच दीर्घकालीन सहयोग की दिशा में ठोस कदम साबित होगा और दोनों पक्षों के बीच औद्योगिक, व्यापारिक और सांस्कृतिक साझेदारी को नई गति देगा। उल्लेखनीय है कि आसियान (एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन्स) दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय संगठन है। इसका उद्देश्य सदस्य देशों के बीच आर्थिक सहयोग, व्यापार, सुरक्षा, सांस्कृतिक संबंध और क्षेत्रीय स्थिरता को मजबूत करना है। आसियान में 10 देश सदस्य हैं, जिनमें इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फिलीपींस, वियतनाम, म्यांमार, कम्बोडिया,लाओस और ब्रुनेई शामिल हैं।

ईपीएस 95 पेंशनर्स में भारी असंतोष

भोपाल। आश्वासन के बावजूद मेडिकल सुविधा और 7500+डीए की घोषणा नहीं होने पर ईपीएस 95 पेंशनर्स में भारी नाराजगी व्याप्त है। ईपीएस 95 पेंशनर्स एसोशियेसन के राष्ट्रीय महासचिव अरुण वर्मा ने बताया की ईपीएस 95 पेंशनर्स द्वारा विगत कई वर्षों से रुपये 7500+डीए एवं मेडिकल सुविधा के लिए विगत कई वर्षों से आंदोलन किया जा रहा है लेकिन भारत सरकार द्वारा अश्वासन मौखिक एवं लिखित मे अश्वासन देने के बाद भी अभी तक रुपये 7500+ डीए की घोषणा नही की गई है। ईपीएस 95 पेंशनर्स मे भारी असंतोष व्याप्त है जिसकी वजह से राष्ट्रीय संघर्ष समिति द्वारा 3 एवं 4 दिसम्बर 2025 को जंतर मंतर दिल्ली मे पेंशनर्स द्वारा आंदोलन किया जाएगा। जिसमे हजारों की तादाद मे पेंशनर्स शामिल होंगे। राष्ट्रीय ईपीएस 95 पेंशनर्स एसो. के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुभाष शर्मा एवं राष्ट्रीय महासचिव अरुण वर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी एवं केंद्रीय श्रम मंत्री से अनुरोध किया है कि ईपीएस 95 पेंशनर्स के लिए तत्काल रुपये 7500+डीए एवं मेडिकल सुविधा की घोषणा की जाए। अनुरोध करने वालों मे अजय श्रीवास्तव, आरएन कौल, एससी उपाध्याय, आरएस रघुवंशी, एके व्योहार, पी एल शर्मा, एससी त्रिपाठी, श्याम सुन्दर शर्मा, चंद्रभान राय, एसएस तिवारी, हतिम अली अंसारी, पीसी जैन, एसके शर्मा, व्हीके शुक्ला, एसके जोशी, श्रीमती शिल्पा फडणवीस, वीणा जोशी और आरपी पाण्डे आदि शामिल हैं।

केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले- देश में देसी से ज्यादा विदेशी मुसलमान

अमरकंटक में कहा- यही देश के खिलाफ आंदोलन कर पाकिस्तान की मदद करते हैं

अनूपपुर (नप्र)। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने रविवार को अनूपपुर जिले के अमरकंटक प्रवास पर है। इस दौरान उन्होंने मां नर्मदा के उद्गम स्थल पर पूजा-अर्चना की और देश-प्रदेश की सुख-समृद्धि की कामना की। इसके बाद वे सर्किट हाउस पहुंचे, जहां आयोजित बैठक में उन्होंने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय जनजाति विश्वविद्यालय और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयास से 2000 लोगों को रोजगार से जोड़ने की योजना की जानकारी दी। मंत्री ने यहां गोंड आर्ट से बनी चित्रकलाओं का अवलोकन भी किया।

घुसपैठियों पर जांच की मांग- अपने प्रवास के दौरान केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और अन्य राज्यों में अवैध घुसपैठ की स्थिति चिंता का विषय है और इसपर गंभीरता से जांच की जरूरत है।

अमरकंटक में मुस्लिम आबादी बढ़ने को लेकर उन्होंने सवाल उठाते हुए कहा मैं अमरकंटक लगभग 25 सालों से आ रहा हूं। जब मैं पहली बार 1998 में आया था, तब यहां एक भी मुस्लिम परिवार नहीं था। अब यह अचानक कैसे बढ़ गए?

उन्होंने कलेक्टर से बाहरी लोगों की जांच करने की मांग की। केंद्रीय मंत्री ने देश के मुसलमानों से अपील की कि वे इन घुसपैठियों को संरक्षण न दें। उन्होंने कहा, जब कोई पूछता है तो आप कह देते हैं कि यह मेरे खाला का लड़का है।

आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर से शुरू हुआ

● शशि थरूर बोले-अब दिल्ली-मुंबई तक फैल गया

श्रीनगर (एजेंसी)। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा रविवार को कहा, आतंकवाद 1989-90 में कश्मीर से शुरू हुआ और धीरे-धीरे मुंबई, पुणे, दिल्ली तक फैल गया है। भारत पिछले 30 साल से आतंकवाद से चुनौती झेल रहा है। अब इस पर कठोर और असरदार ऐक्शन की जरूरत है। उन्होंने कहा- हर आतंकी घटना में दो चीजें बेहद अहम होती हैं। यह पता लगाना कि वारदात किसने और क्यों की और ऐसे हमलों को दोबारा होने से रोकने के उपाय। हर मुद्दे को युद्ध और शांति के चश्मे से नहीं परखा जा सकता। आतंकवाद पर सख्ती जरूरी है, लेकिन देश के विकास के बड़े लक्ष्य को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए।

रूसी क्रूड ऑयल का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार भारत

● अक्टूबर माह में 22.17 हजार करोड़ का इम्पोर्ट किया

नई दिल्ली (एजेंसी)। भारत ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बार-बार आपत्तियों के बावजूद रूस से क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल खरीदना जारी रखा है। अक्टूबर में रूस से 2.5 बिलियन डॉलर (करीब 22.17 हजार करोड़ रुपए) वैल्यू का कच्चा तेल देश में आया, जिससे भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार बन गया है। यह जानकारी हेलसिंकी स्थित सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर ने अपनी रिपोर्ट में दी है। रिपोर्ट के अनुसार, चीन 3.7 बिलियन डॉलर (करीब 32.82 हजार करोड़ रुपए) के इम्पोर्ट के साथ पहले नंबर पर रहा। कुल मिलाकर, रूस से भारत का फॉसिल फ्यूल आयात 3.1 बिलियन डॉलर (करीब 27.49 हजार करोड़) पहुंच गया है, जबकि चीन का कुल आंकड़ा 5.8 बिलियन डॉलर (करीब 51.44 हजार करोड़) रहा। अमेरिकी प्रतिबंध का असर दिसंबर के आंकड़ों में दिख सकता है।

रिलायंस समेत 5 बड़ी कंपनियां रूसी तेल नहीं खरीदेंगी

भारत ने दिसंबर महीने की डिलीवरी के लिए रूस से कच्चे तेल की खरीद में बड़ी कटौती की है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, देश की पांच प्रमुख रिफाइनर कंपनियों ने दिसंबर के लिए कोई नया ऑर्डर नहीं दिया है। यह फैसला अमेरिकी प्रतिबंधों और भारत-अमेरिका व्यापार वार्ताओं के बीच लिया गया है। अगस्त में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने रूसी तेल खरीदने के कारण भारत पर 50 फीसदी टैरिफ लगा दिया था। इसके बाद उन्होंने रूस की सरकारी तेल कंपनी रोसनेफ्ट और लुकोइल के साथ सभी तरह के लेन-देन को प्रतिबंधित कर दिया।

मुझे गंदा कहा, मारने के लिए चप्पल तक उठाई

● रोहिणी बोलीं-कहते हैं, टिकट-पैसे लेकर गंदी किडनी दी ● लालू की बेटी ने कहा-मैंने बच्चों तक की परवाह नहीं की

पटना (एजेंसी)। बिहार विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद लालू परिवार में टकराव बढ़ गया है। राजनीति छोड़ने और अपने परिवार से नाता तोड़ने के ऐलान के एक दिन बाद रोहिणी आचार्य ने एक के बाद एक 2 सोशल मीडिया पोस्ट कर तेजस्वी यादव और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। आज रविवार सुबह रोहिणी ने एक इमोशनल पोस्ट कर कहा- मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया। मुझे अनाथ बनाया गया।

मैंने रोते-रोते घर छोड़ा है। मुझे मारने के लिए चप्पल उठाई गई। मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया। आप सब मेरे रास्ते कभी न चलें, किसी घर में मेरे जैसी बेटी-बहन न हो। इस पोस्ट के रोहिणी ने लालू को किडनी देने वाले फोटो-वीडियोज को फेसबुक पर पिन भी किया।

पिता को किडनी देने को गंदा बताया गया- दूसरे पोस्ट में रोहिणी ने लिखा- कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी। सभी बेटी -बहन, जो शादीशुदा हैं, उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा-भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोलें कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे। सभी बहन बेटियां अपना घर-परिवार देखें, अपने माता-पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें। मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनों बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली। अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया। आप सब मेरे जैसी गलती, कभी, न करें किसी घर रोहिणी जैसी बेटी न हो। इससे पहले शनिवार देर रात उन्होंने रोते-रोते राबड़ी आवास भी छोड़ दिया। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत में रोहिणी ने कहा, मेरा कोई परिवार नहीं है।

परिक्रमा

'उमंग' और 'दीपक' क्या बचा पायेंगे आदिवासियों में कांग्रेस का जनाधार

अरुण पटेल

लेखक
सुबह सवेरे के
प्रबंध संपादक हैं

मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ में सत्ता का रास्ता आदिवासियों के बीच से होकर गुजरता है और आदिवासी वर्ग जिसका साथ देता है वह सत्ता के अधिक करीब पहुंच जाता है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव तथा छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय का समूचा ध्यान अब आदिवासी समुदाय के बीच भाजपा की मजबूत पैठ बनाने का है ताकि यह वर्ग कांग्रेस से दूर हटे और भाजपा से जुड़े। वैसे कुछ अंचलों में आदिवासियों का एक बड़ा समूह भाजपा से जुड़ भी चुका है लेकिन अभी भी कांग्रेस की उन पर पकड़ जारी है। क्योंकि आदिवासियों के मन-मस्तिष्क में अभी तक इंदिरा गांधी की यादें ताजा हैं। छत्तीसगढ़ में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज तथा मध्यप्रदेश में राज्य विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार आदिवासी वर्ग से हैं इसलिए दोनों राज्यों में इन दोनों की जिम्मेदारी अधिक है ताकि यह दोनों आदिवासी वर्ग से अपनी पार्टी को जोड़ कर रख सकें। इसी पर भरोसा कर पार्टी ने इन्हें कहीं संगठन तथा कहीं विधायी पक्ष का चेहरा बनाया हुआ है। जहां तक उमंग सिंघार का सवाल है उनके पीछे दिग्विजय सिंह सरकार में उपमुख्यमंत्री और बाद में नेता प्रतिपक्ष रहीं जमुनादेवी की लम्बी चौड़ी विरासत है जबकि दीपक बैज भी आदिवासी बहुल बस्तर संभाग से आते हैं।

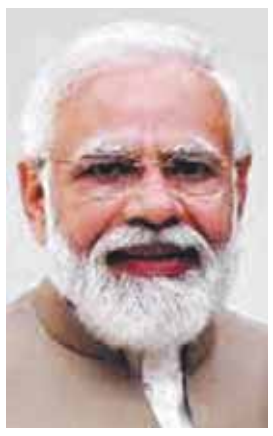

जनजाति गौरव दिवस का भाजपा ने बड़े पैमाने पर आयोजन किया और जबलपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने सौगातों की मूसलाधार झड़ी लगा दी तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपने वर्चुअल सम्बोधन में कांग्रेस पर आरोप लगाया कि उसने छः दशकों तक आदिवासियों को हाशिए पर रखा है। उनका कहना था कि स्वतंत्रता संग्राम में आदिवासी समाज ने अपना लहू बहाया है और आदिवासी क्रांतिकारियों के योगदान से स्वतंत्रता संग्राम के अध्याय भरे पड़े हैं लेकिन कुछ लोगों के परिवार को आजादी का श्रेय देने के साथ क्रांतिकारियों के बलिदान और त्याग व तपस्या को भुला दिया गया है। मोदी का कहना था कि 2014 के पहले कोई शहीद बिरसा मुंडा के बलिदान को याद नहीं करता था यह परम्परा हमने शुरु की। जनजाति गौरव अगली पीढ़ियों को बताने के लिए म्यूजियम बनाया। जनजाति समाज की बोली व संगीत को संरक्षित किया जायेगा। आदिवासी वर्ग की ही छतरपुर की क्रांति गौड़ जो महिला विश्व कप क्रिकेट विजेता टीम की अहम् सदस्य थीं को उन्होंने एक करोड़ रुपये का चेक दिया। इसके साथ ही आदिवासियों में विशेष सम्मान रखने वाली वीरांगना रानी दुर्गावती के नाम पर प्रदेश के सभी बालिका आश्रम व छात्रावासों के नाम रखे जायेंगे। बालक आश्रमों का नाम शहीद राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह के नाम पर होगा। पांच हजार छात्रावास अधीक्षकों की नियुक्ति करने की घोषणा भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने की। मोहन यादव ने आदिवासियों के बीच कहा कि राष्ट्र के स्वाभिमान और स्वतंत्रता पर जब प्रश्न खड़े हुए तब जनजाति समुदाय सबसे आगे खड़ा रहा। प्रदेश में आदिवासी बलिदानियों की समृद्ध परम्परा रही है। रानी दुर्गावती, राजा शंकर शाह , रघुनाथ शाह , बाजा नायक, भीमा नायक, टंट्या मामा ने जल, जंगल, जमीन बचाने व देश की स्वाधीनता के लिए लम्बी लड़ाई लड़ी। मुख्यमंत्री यह भी याद दिलाने से नही चूके कि जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री बने तो जनजाति मंत्रालय बनाया गया। जबकि कांग्रेस ने उन्हें दस साल तक हाशिए पर रखा तथा भाजपा ने बजट बढ़ाया। मैंने स्वयं भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली की मिट्टी से तिलक कर आदिवासी कल्याण का संकल्प लिया था और स्किल सेल बीमारी से निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चल रहा है। वे यह भी बताने से नहीं भूले कि आखिर भाजपा सरकार ने आदिवासियों के लिए क्या-क्या किया। रानी दुर्गावती की जयंती पर जबलपुर व सिंग्रामपुर में और क्रांति नायक भभूत सिंह के स्थान पर पचमढ़ी में केबिनेट बैठक की। टंट्या मामा के नाम खरगोन में विश्वविद्यालय खोला गया। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में टंट्या मामा के नाम पर रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी किया गया। जनजाति कल्याण की जितनी योजनायें हो सकती हैं उन पर सरकार काम कर रही है।

राहुल का सख्त संदेश और भाजपा का तंज

नर्मदापुरम जिले जो पहले होशंगाबाद जिला था में सतपुड़ा पर्वत माला पर स्थित पचमढ़ी में कांग्रेस के जिलाध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में राहुल गांधी ने जो सख्त संदेश दिया है उस पर क्या वे कांग्रेस में अमल करा पायेंगे। यह शिविर पूरी तरह से प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष महेंद्र जोशी की देखरेख में हुआ और आयोजन की तैयारी भी उन्होंने ही कराई। यह यक्ष प्रश्न है कि क्या अलग-अलग दिशाओं में अपनी अंध महत्वाकांक्षाओं के घोड़े दौड़ाने वाले कांग्रेस नेताओं को राहुल एक दिशा में घोड़े दौड़ाने को विवश कर पायेंगे, क्योंकि इनकी यह आदत कई दशकों से पड़ी हुई है। उनका सख्त संदेश था कि गुटबाजी और ऐकला चलो की नीति अब नहीं चलेगी, अब एकजुटता व समन्वय बनाने के साथ सहमति के आधार पर निर्णय लिये जायें। जो नया नेतृत्व तैयार हो रहा है वह वरिष्ठ नेताओं की अनदेखी न करे। विधानसभा चुनाव में अभी समय है इसलिए जिलाध्यक्ष दो साल में बूथ स्तर तक संगठन खड़ा करें फिर मिशन 2028 यानी विधानसभा चुनाव की तैयारी होगी। जिलाध्यक्ष संगठन बनाते समय क्या वास्तव में मैदानी कार्यकर्ताओं को ढूंढ पायेंगे या उनकी दृष्टि भी उनकी ही गणेश परिक्रमा करने वाले और ड्राइंग रुम की शोभा बढ़ाने वाले लोगों तक ही जायेगी। जमीन से कटे और नेताओं से जुड़े कार्यकर्ता ही यदि तवज्जो पा गये तो फिर राहुल गांधी के संदेश पर अमल कैसे होगा। जब कांग्रेसी आपस में ही एक-दूसरे का विरोध कर रहे हैं तब यह सवाल उठना स्वाभाविक है कि कांग्रेस क्या इतनी मजबूत हो पायेगी कि वह उस भाजपा का मुकाबला करे जिसका एकमेव लक्ष्य कांग्रेस की जड़ों में मट्ठा डालना है, क्योंकि अभी भी दोनों के मतों के बीच इतना फासला नहीं है कि जिसे कांग्रेस पाट न पाये। दिग्विजय सिंह के इंदौर के कार्यक्रम का एक प्रकार से जिला कांग्रेस द्वारा बहिष्कार करने की बात सामने आई। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव, पूर्व मंत्री और पूर्व विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अजय सिंह हों या डॉ. गोविंद सिंह, एक प्रकार से कांग्रेस में हाशिए पर धकेल दिये गये हैं और पार्टी में अब उनकी इतनी भी पूछपरख नहीं है कि जितना उनका जनाधार है। जहां तक अजय सिंह का सवाल है मध्यप्रदेश के हर जिले व गांव में कोई न कोई उनका समर्थक और प्रशासक इसलिए मिल जाता है क्योंकि वे कांग्रेस के हैवीवेट राजनेता रहे अर्जुन सिंह के राजनीतिक उत्तराधिकारी हैं। जहां तक अरुण यादव का सवाल है उनकी भी अपनी विरासत है और वे सहकारिता क्षेत्र के पुरोधा रहे पूर्व उपमुख्यमंत्री सुभाष यादव के बेटे हैं जिनका प्रदेश में जातिगत आधार भी है इसलिए अरुण यादव का प्रभाव कायम है। गोविंद सिंह भी सहकारिता से जुड़े एक दबंग नेता हैं और उनका भी अपने इलाके में अच्छा जनाधार है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी को कह चुके हैं कि इन सबको साथ लेकर चलना चाहिये। मध्यप्रदेश में आज भी सबसे अधिक व्यापक जनाधार पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का है और उन्होंने भी शिविर में कहा कि ऐकला नहीं सबको साथ लेकर चलना होगा। यही कारण है कि राहुल गांधी ने समन्वय बनाकर सामूहिक निर्णय पर जोर दिया। लेकिन इस पर कितनी ईमानदारी से अमल होता है यह देखना भी राहुल की ही जिम्मेदारी होगी। अब देखने वाली बात यही होगी कि उनके दिए गये सख्त संदेश का अमल किस प्रकार होता है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा है कि राहुल गांधी ने समन्वय पर जोर दिया है और साथ ही यह भी निर्देशित किया है कि योग्यता से कोई समझौता नहीं होगा। वहीं दूसरी ओर भाजपा सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने तंज किया है कि राहुल गांधी राजनीति को गंभीरता से नहीं लेते हैं। बिहार चुनाव के बीच मध्यप्रदेश में जंगल सफारी का मजा ले रहे हैं। अनुशासन की बात करने वाले राहुल गांधी पहले अपने जीवन में अनुशासन लायें। शायद उनका इशारा राहुल गांधी के शिविर में दस मिनट देरी से पहुंचने और बाद में जंगल सफारी का आनंद लेने की ओर था।

और यह भी

राहुल गांधी ने देरी से आने के लिए शिविर के इंचार्ज से पूछा कि मेरे लिए क्या सजा है और उन्हें दस पुशअप करने की सजा दी गयी जिसे राहुल गांधी ने स्वीकार किया। शायद वे यह संदेश देना चाहते थे कि कांग्रेस में राहुल से लेकर आम कार्यकर्ता तक सभी समान हैं और सबको अनुशासन में रहकर एक ही लक्ष्य की ओर बढ़ना होगा तथा मैदानी स्तर तक कांग्रेस की मजबूती के लिए जुटना होगा। वहीं दूसरी ओर अलीराजपुर के जनजाति गौरव दिवस के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि यह दिवस हमारे लिए दीपावली और होली की तरह है। इसका मतलब साफ हो जाता है कि अब भारतीय जनता पार्टी का समूचा ध्यान कांग्रेस से आदिवासी वोट बैंक अधिक से अधिक छीन लेने का है और कांग्रेस के अंदर जो आदिवासी चेहरे हैं उनकी जिम्मेदारी इसीलिए ही बढ़ जाती है।

भोपाल में 6 लाख तक के नकली नोट खपाए

किराना दुकानों, पान की गुमटियों पर देता था आरोपी, 30 लाख के नोट छापने की तैयारी में था

भोपाल (नप्र)। भोपाल में नकली नोट खपाने वाले विवेक यादव ने पुलिस की पूछताछ में कई खुलासे किए हैं। वह शहर के आउटरों में बनी छोटी किराना दुकानों, पान की गुमटियों और चाय-नाश्ते की होटलों पर इन नोटों को खपाता था।

उसने रायसेन रोड, 11 मील, बैरसिया रोड का ईंटखेड़ी गुनगा, परवलिया सड़क, एयरपोर्ट रोड, गांधी नगर, पिपलानी, अवधपुरी समेत कई इलाकों में नोट चलाए हैं। आसपास के जिलों में भी उसने नोट चलाए हैं। खास बात यह है कि वह एक दिन में सिर्फ 3 से 4 नकली नोट ही चलाता था।

आरोपी विकास के घर की तलाशी में पुलिस को 500 रुपए के 428 नकली नोट मिले हैं। पुलिस को उसके पास से 30 लाख से ज्यादा के नकली नोट छापने का रॉ मटेरियल भी मिला है।

पूछताछ में उसने नकली नोट खपाने के तरीके बताए हैं। यह भी बताया कि उसने नकली नोटों में अधिक सफाई लाने के लिए रकम जुटाकर महंगे उपकरण खरीदे थे।

आरोपी पिपलानी इलाके में शुक्रवार शाम को शांति नगर झुग्गी बस्ती के पास एक दुकान पर दोबारा नोट चलाने गया था। जहां उसे पहचान लिया गया। इसके बाद पुलिस को सूचना दे दी।पूछताछ के बाद पुलिस ने आरोपी को शनिवार को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया है।

अब तक 6 लाख के नकली नोट चलाए- एडिशनल डीसीपी गौतम सोलंकी ने बताया कि आरोपी दुकानों पर जाने के बाद 20 से 50 रुपए के बीच का सामान खरीदता था। इसके लिए वह पांच सौ रुपए का नोट दिया करता था। दिन भर में वह तीन से चार अलग-अलग दुकानों पर इसी तरह से नोट चलाता था।

जब उसने जरूरत की चीजें नकली नोटों के बल पर जुटा लीं तो अय्याशी करना शुरू कर दिया। शहर के अलग-अलग होटलों में महंगे खाने से लेकर मॉल से कपड़ों की खरीददारी तक इसी रकम से कर डाली। इस तरह आरोपी करीब 6 लाख रुपए के नकली नोट मार्केट में खपा चुका है।

विदिशा-सीहोर रायसेन में भी खपाए नोट- आरोपी नकली नोट खपाने विदिशा, सीहोर और रायसेन तक जा चुका है। वह चार से पांच हजार रुपए के नकली नोट लेकर घर से निकलता था। आधे नोट खपाने के बाद घर लौट आता था। पकड़ा न जाए इसके लिए उसने अपने काम में कोई पार्टनर नहीं बनाया था। नोटों की छपाई से लेकर खपाने काम अकेले ही अंजाम देता था।

मध्यप्रदेश बना भारत का फूड-बास्केट, कृषि विकास में रचा नया इतिहास

भोपाल (नप्र)। कभी 'बीमारू राज्य' और विकास की दौड़ में पिछड़ा माना जाने वाला मध्यप्रदेश आज आत्मनिर्भरता, कृषि समृद्धि और तीव्र आर्थिक विकास का प्रतीक बन चुका है। यह परिवर्तन मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के दूरदर्शी नेतृत्व, सरकार की योजनाबद्ध नीतियों और किसानों की अटूट मेहनत का परिणाम है। मध्यप्रदेश अब न केवल विकास दर में अग्रणी है, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में भी देश में नई पहचान बना चुका है। यही कारण है कि भारत का हृदय प्रदेश अब देश का नया 'फूड-बास्केट' कहलाने लगा है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव का कहना है कि मध्यप्रदेश ने कृषि और उससे सम्बद्ध क्षेत्रों में जो आशातीत प्रगति की है, उसमें हमारे अन्नदाताओं की महती भूमिका है। बीते वर्षों में मध्यप्रदेश ने कृषि उत्पादन, सिंचाई विस्तार और किसानों की आय वृद्धि के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल कर देश का नया 'फूड बास्केट' बनने का गौरव प्राप्त किया है। राज्य की विकास दर अब डबल डिजिट में पहुंच चुकी है, जिसमें कृषि एवं सम्बद्ध क्षेत्रों का सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने का संकल्प लिया है। सिंचाई सुविधाओं का विस्तार, पर्याप्त बिजली आपूर्ति, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी, भावांतर भुगतान योजना और कृषि यंत्रीकरण ने किसानों से जीवन में खुशहाली आ रही है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि आज मध्यप्रदेश गेहूं, चना, मसूर, सोयाबीन और तिलहन उत्पादन में देश में अग्रणी बन चुका है। पंजाब और हरियाणा जैसे परम्परागत कृषि सम्पन्न राज्यों को कई फसलों के उत्पादन में पीछे छोड़ना राज्य के किसानों की मेहनत और सरकार की संवेदनशील नीतियों का ही परिणाम है। हमने कृषि के साथ-साथ डेयरी, पशुपालन, मत्स्य पालन और खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्रों में भी राज्य ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ,एग्रो एंड फूड प्रोसेसिंग इकाइयां और कोल्ड स्टोरेज चेन जैसे अनेक कदम किसानों को उनके उत्पादों का बेहतर मूल्य दिलाने में मददगार सिद्ध हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमारा लक्ष्य बिल्कुल स्पष्ट है - हर खेत तक पानी, हर किसान तक प्रगति और हर घर तक समृद्धि। मध्यप्रदेश का किसान अब सिर्फ़ अन्नदाता नहीं, बल्कि खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भर भारत का निर्माणकर्ता बन चुका है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने किसानों, कृषि वैज्ञानिकों और राज्य के पूरे कृषि अमले को इस राष्ट्रीय उपलब्धि की ओर बढ़ने के लिए बधाई दी है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में मध्यप्रदेश देश की खाद्य सुरक्षा को सशक्त करेगा, बल्कि वैश्विक कृषि मानचित्र पर भी अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करेगा।

कृषि समृद्ध प्रदेश बनने की कहानी- कभी सीमित सिंचाई साधनों, अस्थिर बिजली आपूर्ति और अपर्याप्त अवसंरचना के कारण मध्यप्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था घाटे में चल रही थी। किसानों की आमदनी सीमित थी और ग्रामीण जीवन में भी कुछ कठिनाइयां थीं। परंतु बीते दो दशकों में परिदृश्य पूरी तरह बदल गया है। सरकार ने कृषि और ग्रामीण विकास को अपनी नीतियों के केंद्र में रखकर जो कार्य किया, उसने राज्य की तस्वीर ही बदल दी। हाल ही में हुए आर्थिक सर्वेक्षण में मध्यप्रदेश ने 24 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की है, जो राष्ट्रीय विकास औसत से कहीं अधिक है। यह प्रगति बताती है कि मध्यप्रदेश अब आत्मनिर्भरता की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

कृषि विकास में आई नई क्रांति- मध्यप्रदेश में सबसे ज्यादा विकास कृषि क्षेत्र में देखा गया है। बीते वर्षों में राज्य सरकार ने कृषि को सिर्फ़ आजीविका का साधन नहीं, बल्कि समृद्धि का आधार बनाने का संकल्प लिया। किसानों को फसल उत्पादन की लागत में राहत देने, खेती को लाभकारी बनाने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए कई योजनाएं लागू की गईं। कृषक कल्याण मिशन के जरिए किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए सभी जतन किए जा रहे हैं। भावांतर भुगतान योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, फसल बीमा योजना तथा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर फ़सल खरीदी और इस खरीदी पर बोनस राशि भी देने जैसे प्रयासों ने किसानों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान की है। इसके अलावा उन्नत कृषि उपकरणों पर सब्सिडी और प्राकृतिक एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने की कोशिशों ने भी खेती-किसानी को और अधिक रूचिकर, उत्पादक और टिकाऊ बनाया है। राज्य में सिंचाई सुविधाओं का खेत तक विस्तार भी एक मील का पत्थर साबित हुआ है। नर्मदा घाटी विकास परियोजना, पार्वती-कालीसिंध-चंबल नदियों को आपस में जोड़ने और केन-बेतवा राष्ट्रीय नदी लिंक जैसी परियोजनाओं से लाखों हेक्टेयर कृषि क्षेत्र को सिंचाई सुविधा के दायरे में लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति के सुदृढ़ीकरण से रबी सीजन में फसलों की उत्पादन क्षमता कई गुना बढ़ गई है।

खेती-किसानी की बदलती परिभाषा- मध्यप्रदेश के किसान अब पारम्परिक खेती तक सीमित नहीं हैं। वे नई तकनीकों और आधुनिक कृषि पद्धतियों को अपनाकर उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार ला रहे हैं। ड्रिप इरिगेशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग, मल्टीक्रॉपिंग और फसल विविधीकरण जैसे नवाचारों ने कृषि को एक व्यावसायिक रूप दिया है। प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालयों, अनुसंधान केंद्रों और कृषि विज्ञान केंद्रों की सक्रिय भूमिका ने किसानों को नवीनतम जानकारी सहित प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया है। अब किसान बाजार की मांग के अनुसार फसलें पैदा कर रहे हैं और निर्यात की दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं।

बीजेपी विधायक रामेश्वर बोले-

आज के अपराधी पूरे शिक्षित

रामेश्वर ने दिल्ली बम ब्लास्ट पर कहा- आरोपी डॉक्टरों की 3 पीढ़ियां बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगी

भोपाल (नप्र)। छह दिन पहले 1 नवंबर की शाम को दिल्ली में लाल किले के पास कार में हुए बम धमाके में 12 लोगों की मौत हुई थीं और दर्जन भर लोग घायल हुए थे। इस घटना के आठ आरोपियों में से 5 डॉक्टर हैं। बम धमाके में डॉक्टरों के संलिप्त पाए जाने पर भोपाल की हुजूर सीट से बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखा हमला बोला है।

भोपाल के कुशाभाऊ ठाकरे सभागार में मानसरोवर ग्लोबल यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में स्टूडेंट्स को संबोधित करते हुए विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा, दिल्ली में जिन बेईमानों ने जो हरकत की है। उन्होंने भरोसे को ही नहीं तोड़ा, बल्कि हिन्दुस्तान के आम व्यक्ति के मन में ये भरोसा जागृत हो गया कि कल हम लोग कहते थे कि अपराध वो लोग करते हैं जो अशिक्षित हैं लेकिन, आज के अपराधी जो पकड़े गए हैं वे पूर्णतः शिक्षित हैं।

पाक परस्त डॉक्टरों की तीन पीढ़ियां बच्चे पैदा नहीं कर पाएंगी- रामेश्वर शर्मा ने कहा, जिन्हें समाज की चिकित्सा करनी चाहिए थी। अब ऐसा लग रहा है कि पुलिस के डंडे को उनका इलाज करना चाहिए। नरेंद्र मोदी की सरकार वो व्यवस्था कर रही है। उन अपराधियों की वो चिकित्सा होगी।

चिंता मत करना हमारे डॉक्टर गरीबों का इलाज करेंगे। पाकिस्तान के टुकड़ों पर पलने वाले डॉक्टरों हम तुम्हारा ऐसा इलाज करेंगे कि तीन पीढ़ियां बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगी इस बात को ध्यान रखना।

कोई व्यक्ति भरोसा तोड़ता है तो समाज दुखी होता है- रामेश्वर शर्मा ने कहा, शिक्षा एक बहुत बड़ा संस्कार और भरोसा है जब कोई व्यक्ति इस तरह भरोसा तोड़ता है तो समाज दुखी होता है। मैं भरोसे के साथ कह सकता हूं कि आज जो डिग्रियां लेकर जा रहे हैं वे भरोसे को कायम रखेंगे। भारत का नेक नागरिक बनकर पगड़ी की लाज रखेंगे। इसको कभी नीचा नहीं होने देंगे।

रेलवे ने इज्तिमा के लिए किए इंतजाम

भोपाल-बिलासपुर और भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस में दो दिन अतिरिक्त सामान्य कोच

भोपाल (नप्र)। आलमी तब्लीगी इज्तिमा के दौरान यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए पश्चिम मध्य रेलवे, भोपाल मंडल ने विशेष भीड़ प्रबंधन के तहत दो प्रमुख ट्रेनों में अतिरिक्त सामान्य कोच जोड़ने का निर्णय लिया है।

यह व्यवस्था 17 व 18 नवंबर 2025 को लागू रहेगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार इज्तिमा के दिनों में भोपाल स्टेशन सहित पूरे मंडल में यात्रियों की आवाजाही में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होती है, ऐसे में भीड़ को नियंत्रित रखने और यात्रियों को बेहतर सुविधा देने के लिए यह कदम उठाया गया है।

इन ट्रेनों में लगेंगे अतिरिक्त कोच

ट्रेन संख्या 18235 - भोपाल-बिलासपुर एक्सप्रेस- 17 और 18 नवंबर 2025, इसमें 1 अतिरिक्त सामान्य कोच जोड़ा जाएगा।

ट्रेन संख्या 14814 - भोपाल-जोधपुर एक्सप्रेस = 17 व 18 नवंबर 2025, इसमें भी 1 अतिरिक्त सामान्य कोच लगाया जाएगा।

इज्तिमा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग भोपाल पहुंचे हैं।।

इज्तिमा में शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में लोग भोपाल पहुंचे हैं।।

दोनों ट्रेनों में एक-एक कोच जोड़ा है

सीनियर डीसीएम सौरभ कटारिया ने बताया कि इज्तिमा अवधि में यात्रियों की संख्या में वृद्धि को देखते हुए दोनों ट्रेनों में एक-एक अतिरिक्त सामान्य कोच जोड़कर भीड़ का प्रभावी प्रबंधन सुनिश्चित किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि रेलवे प्रशासन यात्रियों से सहयोग की अपील करता है, ताकि यात्रा सुगम और सुरक्षित रहे। रेल मंडल ने यात्रियों को सलाह दी है कि अतिरिक्त कोचों व ट्रेन से संबंधित अद्यतन जानकारी स्टेशन पर उपलब्ध सूचना केंद्रों के साथ-साथ रेल मदद 139 और अन्य ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी प्राप्त की जा सकती है।

संपादकीय

बिहार विजय में एमपी का योगदान

बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए और भाजपा की प्रचंड जीत में मप्र के भाजपा नेताओंका भी अहम योगदान है। एमपी से कुल 75 भाजपा नेता मैदान में उतारे गए थे और सभी ने अपने अपने पिचों पर जबर्दस्त बैटिंग करते हुए भाजपा को राज्य में नंबर वन पार्टी बना दिया। हालांकि प्रचार तो बिहार में मप्र के कांग्रेस नेताओं ने भी किया, लेकिन नतीजा शून्य रहा। जबकि भाजपा का परफार्मेंस जबर्दस्त रहा और मप्र के बीजेपी नेताओं ने वहां भी अपना संगठन कौशल दिखाया। इस टीम एमपी के सरताज थे राज्य के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव। मोहन यादव को बिहार की कुल 26 सीटों पर चुनाव प्रचार की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इनमें से कई यादव बहुल थीं। इनमें से 21 सीटों पर भाजपा ने जीत का परचम फहरा दिया। मोहन यादव ने भाजपा ही नहीं, एनडीए के दूसरे घटक दलों के प्रत्याशियों का भी प्रचार किया। लक्ष्य एक ही था कि राजद के यादव बैंक में सेंध लगाना। वैसे भाजपा ने डॉ.मोहन यादव को बिहार में चुनाव से पहले ही सक्रिय कर दिया था। वो राजनीतिक के साथ सामाजिक कार्यक्रमों में भी भाग ले रहे थे। चुनाव प्रचार के दौरान डॉ. मोहन यादव ने लगभग आधे बिहार में 28 सभाएं और रोड शो किए। इसी प्रकार केन्द्रीय मंत्री व मप्र के पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी जिन सात सीटों पर प्रचार किया, उन सभी पर जीत मिली। पूर्व गृहमंत्री डॉ नरोत्तम मिश्र और मौजूदा खेलमंत्री विश्वास सारंग ने जिन 6-6 सीटों पर प्रचार किया, वो सभी भाजपा की झोली में गई। पार्टी ने मप्र से सांसद व पूर्व प्रदेशाध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा, प्रदेश के संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा और प्रदेश प्रभारी डा. महेंद्र सिंह सहित अन्य नेताओं व कार्यकर्ताओं को बिहार भेजा था। इन्होंने सभा, रोड शो के साथ बूथ प्रबंधन का काम किया। विष्णु दत्त शर्मा को 19 विधानसभा सीटों की जिम्मेदारी दी थी। इनमें से 17 पर एनडीए को जीत मिली। हितानंद और डा. महेंद्र सिंह को तिरहुत और मिथिला क्षेत्र की 58 सीटों की जिम्मेदारी दी गई थी। नतीजा रह रहा कि तिरहुत क्षेत्र की 28 में से 26 और मिथिला की 30 में से 24 सीटें एनडीए ने जीत लीं। वीडी शर्मा ने पटना-बेगूसराय में सीटें जीतकर 89.5त्न का धमाकेदार स्ट्राइक रेट पेश किया। पटना और बेगूसराय जैसे बेहद कठिन मैदानों पर शर्मा ने लगभग एक महीने तक डेरा डालकर बूथ मैनेजमेंट किया और महागठबंधन से भी 8 सीटें छीनकर एनडीए के खाते में डाल दीं। इसी तरह अरविंद भदौरिया (गोपालगंज), अनिल फिरोज़िया (गया), गजेन्द्र पटेल (खगड़िया), डॉ. केपी यादव (समस्तीपुर) लगातार रन बनाते रहे। गौरतलब है कि भाजपा ने इस चुनाव में बिहार को प्रचार की दृष्टि से पांच ज़ोन में बांटा था। सबसे बड़ा ज़ोन मिथिला-तिरहुत जहां मध्यप्रदेश के प्रभारी डॉ. महेंद्र सिंह के नेतृत्व में एमपी की टीम को सौंपा गया था। उधर कांग्रेस ने मप्र से दिग्विजय सिंह और जीतू पटवारी जैसे दिग्गज भेजे जरूर, लेकिन उनकी बैटिंग में जान नहीं दिखी। चुनाव नतीजों के बाद दिग्विजयसिंह ने तो आरोप लगाया कि पूरा खेल वोटर लिस्ट और ईवीएम का था। एसआइआर का खेल हो गया, जैसा कि मेरा शक था, वही हुआ। 62 लाख वोट कटे। 20 लाख जुड़े, उसमें से पांच लाख बिना एसआइआर फार्म भरे ही बढ़ा दिए गए। अधिकतर वोट गरीब, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग के काटे गए। ईवीएम पर तो शंका बनी हुई है। आश्चर्य की बात यह थी कि जब बिहार में चुनाव प्रचार शबाब पर था, उस वक्त कांग्रेस मध्यप्रदेश में नवनियुक्त जिलाध्यक्षों को पचमढ़ी में प्रशिक्षण दे रही थी, बजाए इसके कि इन नेताओं को बिहार में चुनाव प्रचार में लगाया जाता।

नजरिया

रघु ठाकुर
लेखक समाजवादी चिंतक हैं।

बड़बोलापन से नहीं बदलती तस्वीर

इन तीन प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण जरूरी है। निसंदेह अगर बजट की राशि पर निर्धारित करें तो भारत की अर्थव्यवस्था जापान के आगे नजर आयेगी। पंरतु अगर इस राशि का आमजन के बीच बंटवारा और देश के भीतर आदमी-आदमी के बीच के अंतर को देखा जाये तो सरकार का दावा अतार्किक लगता है। क्योंकि यह भी एक तथ्य है कि प्रति व्यक्ति औसत आय की गणना में भारत के प्रति व्यक्ति की औसत आय, दुनिया के 142 देशों के बाद 143वें नंबर पर है। यह अर्थव्यवस्था का कैसा विकास है कि बजटीय राशि याने जीडीपी के आंकड़ों में भारत चौथे नंबर पर है परंतु व्यक्तिगत आय में 143वें नंबर पर है। दरअसल अर्थव्यवस्था के विकास का निर्धारण यह होना चाहिये कि देश के प्रति व्यक्ति की औसत आय बढ़े और विषमता कम हो।

भारत सरकार कुछ दिनों से अपनी पीट थपथपा रही है और देश की आर्थिक तरक्की के आंकड़े प्रस्तुत कर रही है, जिसमें-

1. भारत की अर्थव्यवस्था जापान को पीछे छोड़कर चौथी अर्थव्यवस्था बन गई है, और तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की ओर बढ़ रही है।

2. पिछले 11 वर्षों में भारत सरकार की आर्थिक नीतियों के चलते 27 करोड़ लोग गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर आये हैं।

3. अमेरिका के द्वारा टैरिफदरों में वृद्धि के बाद भारत की अर्थव्यवस्था अप्रभावित रही है।

वैसे तो आज के प्रधानमंत्री जी जब जो जहां जरूरत होती है, वैसे आंकड़ा गढ़ लेते हैं। परंतु इन तीन प्रमुख बिंदुओं का विश्लेषण जरूरी है। निसंदेह अगर बजट की राशि पर निर्धारित करें तो भारत की अर्थव्यवस्था जापान के आगे नजर आयेगी। पंरतु अगर इस राशि का आमजन के बीच बंटवारा और देश के भीतर आदमी-आदमी के बीच के अंतर को देखा जाये तो सरकार का दावा अतार्किक लगता है। क्योंकि यह भी एक तथ्य है कि प्रति व्यक्ति औसत आय की गणना में भारत के प्रति व्यक्ति की औसत आय, दुनिया के 142 देशों के बाद 143वें नंबर पर है। यह अर्थव्यवस्था का कैसा विकास है कि बजटीय राशि याने जीडीपी के आंकड़ों में भारत चौथे नंबर पर है परंतु व्यक्तिगत आय में 143वें नंबर पर है। दरअसल अर्थव्यवस्था के विकास का निर्धारण यह होना चाहिये कि देश के प्रति व्यक्ति की औसत आय बढ़े और विषमता कम हो।

दूसरा कथन सरकार का यह है कि 27 करोड़ देश के लोगों को गरीबी की सीमा से ऊपर उठाया है। अगर सरकार की गणना में एक व्यक्ति का तात्पर्य एक परिवार के मुखिया से है तो फिर इसका मतलब होता है कि लगभग 100 करोड़ से अधिक गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर आ चुके हैं। परंतु स्वतरू सरकार के अनुसार 95 करोड़ लोग देश में ऐसे हैं जो सरकार की रियायतों और प्रधानमंत्री की बोली में कहा जाये तो रेवड़ियों का लाभ उठा रहे हैं, जिनमें 85 करोड़ लोग 5 किलो ग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिमाह मुफ्त अनाज लेने वाले हैं। और 10 करोड़ से अधिक अन्य लाभ यथा लाड़ली बहिना लखपति दीदी आदि। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि सरकार ने पिछले सरकार की तुलना में कोई विकास नहीं किया। मैं मानता हूँ कि सरकार की योजनाओं से देश के एक हिस्से को लाभ पहुँचा है। ग्रामीण रोजगार, प्रशिक्षण संस्थान (आरसेटी) के माध्यम से स्वरोजगार के लिये सरकार द्वारा खोले गये हैं और यह योजना विशेषत ग्रामीण महिलाओं के लिये बहुत लाभप्रद सिद्ध हुई है। गाँव-गाँव में कुछ एक महिलायें और युवा इन ग्रामीण स्वरोजगार केंद्रों से प्रशिक्षित होकर गांवों में अपने घरों के पास स्वरोजगार कर रहे हैं और यह उन्हें एक बड़ा सहयोग है, इस योजना से बच्चियों की आत्मनिर्भरता और आत्मविश्वास बढ़ा है। ग्रामीण स्तर पर स्वसहायता समूह की शुरुआत तो वैसे 80-90 के दशक में बांग्लादेश में मो. यूनुस ने की थी। बाद में दुनिया के अन्य देशों ने उसे अपनाया। निसंदेह यह योजना भारत में भी ग्रामीण रोजगार पैदा कर रही है और ग्रामीण समाज के लिये आजीविका के लिये लाभप्रद सिद्ध हुई है।

वैसे भी हमारे समाज की खानपान, रहन-सहन और जीवनशैली में जो सांस्कृतिक बदलाव आ रहे हैं। उनने तथा परिवारों के विघटन और नये प्रकार के संयोजन ने नये व्यवसायों को गति दी है। आम लोगों के लिये यह व्यवसाय मध्यमवर्गीय संपन्नता और कभी-कभी उच्चवर्गीय संपन्नता की श्रेणी में ला रहे हैं। जैसे खानपान, होटल रेस्त्रा आदि का चलन तेजी से बढ़ा है और स्थिति यह है कि, संपन्न और अमीर तबका आमतौर पर सप्ताह में 2-3 दिन और मध्यमवर्गीय तबका 1-2 दिन घरों पर खाने की बजाय बाहर होटलों पर खाते हैं। इसी प्रकार रोजगार के लिये गांव से पलायन और शहरों में आवागमन के कारण भी कई करोड़ की आबादी खान-पान के लिये होटलों पर निर्भर है। उच्च मध्यमवर्गीय और मध्यमवर्गी समाज के लिये यह होटलों में खाना उनकी संपन्नता का पर्याय है और गरीबों के लिये लाचारी, परंतु इससे इंकार नहीं कर सकते हैं कि यह होटल और ढाबा कल्चर संस्कृति अब बढ़ते-बढ़ते कस्बों और गांव तक पहुंच रही है।

अब यह भी रोजगार करोड़ों लोगों को आमदनी का जरिया है। परंतु जो दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि ये रोजगार बढ़े हैं मध्यमवर्ग की संख्या भी बढ़ी है परंतु आय विषमता उससे बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ी है।

भारत में जहां प्रति व्यक्ति औसत आय 2.50 लाख रुपये प्रतिवर्ष है, वहीं जापान जो आंकड़ों के मुताबिक दुनिया की अर्थव्यवस्था में चौथे नंबर से घटकर पांचवें नंबर पर पहुँच गया है, क्योंकि जापान की जीडीपी लगभग 32 लाख करोड़ रुपये की है और भारत की लगभग 33 लाख करोड़ रुपये, परंतु जापान के प्रति व्यक्ति की वार्षिक आय 29 लाख है और भारत की 2.50 लाख रुपया। जर्मनी की साढ़े सैंतालीस लाख रुपये और अमेरिका की 76 लाख रुपया प्रति व्यक्ति वार्षिक औसत आय है। इसलिये आंकड़ों के खेल हाथी के दाँत के समान दिखाने के अलग होते हैं और खाने के अलग होते हैं। विकास का पैमाना जीडीपी को मानना, अमानवीय पैमाना है। वास्तव में पैमाना तो व्यक्ति की आय का होता है और होना भी चाहिये। देश के 105 करोड़ लोग मोबाइल और इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यह अमीरी का पैमाना नहीं माना जा सकता।

आज से 40 वर्ष पहले जब मोबाइल तकनीक आई थी तब मोबाइल होना अतिसंपन्नता की निशानी थी। आज 5 किलो सरकारी अनाज लेने वाले के हाथ में भी मोबाइल है बल्कि इस मोबाइल के फैलाव के लिये विकास के बजाय एक प्रकार की तकनीक के नशे का विकास मानना चाहिये। इसका एक और महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारत में विषमता तेजी से बढ़ी है। एक तरफ उन अमीरों की संख्या बढ़ी है जो औसतन ढाई सौ से तीन सौ करोड़ रुपये रोज कमा रहे हैं। और दूसरी तरफ ग्रामीण इलाकों में प्रति व्यक्ति आय आज भी मुश्किल से 10 हजार रुपये के आसपास है। इसलिये विषमता को कम करना और आमदनी के अंतर को कम करना यह कसौटी होना चाहिये। परंतु बाजार की ताकतों ने अपने प्रचार के माध्यम से एक नया दर्शन दिया है यूज एंड थ्रो जो भारतीय संस्कृति के प्रतिकूल है। भारतीय संस्कृति उपयोग, संरक्षण और पुनरू उपयोग की रही है जबकि कारपोरेट की संस्कृति उपयोग-दोहन और विनाश की। इस बदलाव से बाजार को लूटने-तिजोड़ी भरने और अपनी संपन्नता बढ़ाने का एक अनंत रास्ता मिल गया है। पहले घर के कपड़े की एक जोड़ी, किताबें, रसोई के बर्तन, कई-कई पीढ़ी चलते थे, यानि जब तक की वे उपयोग होते होते स्वतः समाप्त न हो जायें, तब तक चलते थे।

अब एक व्यक्ति साल में औसतन 10-20 जोड़ी कपड़े बदल लेता है। जरा भी क्षति होने पर उसे फेंक देता है, शिक्षा की किताबें प्रतिवर्ष बदल जाती है। दवाईयां, कृषि आदि की आयु सीमा तय कर दी गई है, जिसके बाद वे स्वतरू अप्रभावी हो जायेगी। अब सेल्फटरमेंनेटर बीज आया है, जो अपने आप नष्ट हो जायेगा। देश के पैमाने पर देखें तो खरबों रुपयों की ऐलोपैथी दवाईयाँ अपने आप काल बाह्य हो रही हैं। अगर विषमता को मिटाना है तो बाजार की अनंत लूट पर बंदिश लगानी होगी। यह कानून मात्र से नहीं बल्कि इसमें एक सामाजिक पहल की भी जरूरत होगी।

हमें यूज एंड थ्रो के बजाय यूज-रीयूज-अमेंड एंड यूज्य की संस्कृति को बढ़ाना होगा।

तीसरी बात, जो अमेरिका द्वारा टैरिफ बढ़ाने का कोई प्रभाव नहीं हुआ है यह सरकारी झूठ है। अनेक उद्योगों के क्षेत्र कठिनाईयों में हैं, जो होना स्वाभाविक भी था। मैं इसे अकेले भारत सरकार को जिम्मेदार नहीं मानता हूँ बल्कि अमेरिका आर्थिक साम्राज्यवाद का हमला मानता हूँ। इसका वस्तुपरक आंकलन निकट भविष्य में होगा। अभी हम अपने देश के साथ हैं और रहेंगे, बस इतनी अपील सरकार से करेंगे कि बड़बोलेपन से हालात नहीं बदलते।

विश्लेषण

योगेश कुमार गोयल
लेखक वरिष्ठ पत्रकार हैं।

एनडीए की 'सुनामी' को क्यों नहीं भांप सके एग्जिट पोल?

नीतियों, संख्या-शास्त्र और राजनीतिक सामाजिक रुझानों को समझने का दावा करने वाले एग्जिट पोल्स एक बार फिर बिहार के जनादेश के सामने बुरी तरह धराशायी हो गए। यह वही बिहार है, जहां जनता की राजनीतिक सूझबूझ देशभर में मिसाल मानी जाती है और इसी बिहार ने 2025 के विधानसभा चुनाव में एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि मतदाता का मन कागजों, ग्राफों और टीवी स्टूडियो की चर्चाओं से नहीं पढ़ा जा सकता। लगभग दो दर्जन एजेंसियों ने अपने-अपने अनुमानों की बौछार कर दी थी लेकिन नतीजों ने इनकी तथाकथित वैज्ञानिकता का मुखौटा एक झटके में उतारकर फेंक दिया। मतदान के बाद तमाम टीवी चैनलों पर जोर-शोर से दावे किए जा रहे थे कि इस बार तस्वीर साफ है, रुझान स्थिर हैं और रणनीति मजबूत है परन्तु असलियत यह थी कि वैज्ञानिक 'सैम्पलिंग' के नाम पर केवल अनुमान बेचे जा रहे थे और इन अनुमानों का आधार जमीन से ज्यादा स्टूडियो-केन्द्रित 'कॉलिनियरिटी' था। हालांकि बिहार के दो चरणों वाले चुनाव में भारी मतदान ने यह संकेत पहले ही दे दिया था कि इस बार कुछ अलग ही लहर है लेकिन यह लहर कितनी प्रचंड होगी, इसे कोई भी एजेंसी अपने सर्वे में नहीं पकड़ सकी। 65 और 68 प्रतिशत की रिकॉर्ड वोटिंग ने विश्लेषकों को जरूर सतर्क किया था लेकिन यह सतर्कता भी उस समय ध्वस्त हो गई, जब एग्जिट पोल्स ने लगभग एक जैसी थाली परोसी यानी एनडीए की जीत लेकिन सीमित मार्जिन के साथ। लगभग सभी 'पोल ऑफ पोल्स' ने एनडीए को 150 के आसपास और महागठबंधन को 80-90 सीटों तक टिका दिया, मानो मतदाता किसी स्थिर पैटर्न में वोट डालने गया हो। इन अनुमानित संख्याओं में न आत्मविश्वास झलकता था, न शोध की गंभीरता। यही नहीं, प्रतिष्ठित मानी जाने वाली एक्सिस माय इंडिया और टुडेज चाणक्य जैसी एजेंसियां भी उस भूचाल को भांप नहीं सकी, जिसने एनडीए को 200 से अधिक सीटों के साथ रिकॉर्ड बहुमत दे दिया। यह पराजय अनुमान की नहीं, समझ की थी और यह विफलता आंकड़ों की नहीं, पद्धति की थी, जो सवाल उठाती है कि क्या एग्जिट पोल्स विश्लेषण करते हैं या महज भविष्यवाणी का खेल खेलते हैं? सबसे दिलचस्प बात यह रही कि सभी एजेंसियों के बीच 'पोल डायरी' नाम की एकमात्र एजेंसी थी, जिसने एनडीए को 184-209 सीटों तक का अनुमान देकर राजनीतिक गलियारों को चौकन्ना कर दिया था। उस समय इसे कई विशेषज्ञों ने 'आउटलायर' कहकर खारिज कर दिया था परंतु नतीजे आए तो वही आउट्लायर सबसे सटीक साबित हुआ। महागठबंधन को 32-49 सीटों का उसका अनुमान भी वास्तविक परिणामों से मेल खा गया। यह सवाल और बड़ा हो जाता है कि जब सारी एजेंसियां एक दिशा में झुकी हों और एक एजेंसी अलग दृष्टि दे रही हो, तब भी आखिर क्यों तथाकथित विशेषज्ञता उस एकमात्र भिन्न अनुमान को गंम्भीरता से नहीं लेती? जवाब स्पष्ट है कि एग्जिट पोल अब एक उद्योग है और उद्योग में जोखिम लेने की जगह कम होती है। सबको उसी लय में बोलना सुविधाजनक लगता है, जिसमें बहुमत की आवाज सुनाई देती है।

बिहार में एक्सिस ने 121-141, चाणक्य ने 148-172, भास्कर ने 145-160, पीपुल पल्स ने 133-159, मैट्रिज-आईएएनएस ने 147-167 और लगभग हर एजेंसी ने 130 से 160 के बीच एनडीए को बांधकर रखा। महागठबंधन को इन्हीं एजेंसियों ने उदारता के साथ 75-110 सीटें सौंप दी, मानो राजनीतिक ध्रुवीकरण, जातीय समीकरणों के पुनर्संयोजन, महिलाओं और युवाओं के मतदान पैटर्न जैसी वास्तविकताओं का कोई महत्व ही न हो। नतीजा जमीन पर वोटर ने इन सारे अनुमानों को 'कागजी गणित' साबित कर दिया। एनडीए जहां 200 सीटों से ऊपर निकल गया, वहीं महागठबंधन 35 के आसपास सिमट गया।

बिहार की राजनीति की जटिलता को समझ पाने में एग्जिट पोल्स की असमर्थता कोई नई बात नहीं है। 2010, 2015 और 2020 में भी वे लगातार विफल रहे। 2015 में जब नीतीश-लालू गठबंधन की प्रचंड जीत हुई थी जबकि सर्वे एजेंसियों ने इसके उलट एनडीए की बढ़त दिखाई थी। 2020 में जब लगभग हर सर्वे ने महागठबंधन की जीत की भविष्यवाणी की थी, तब नतीजों ने एनडीए को 125 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत पर पहुंचा दिया था। अब 2025 में जब एनडीए की सुनामी आई, तब उसे भी पढ़ने में लगभग सभी एजेंसियां एक बार फिर चूक गई। आखिर चुनावी समाजशास्त्र में ऐसी क्या अंधी दीवार है, जो इन एजेंसियों को वास्तविकता से टकराने पर मजबूर कर देती है?

यह विफलता केवल बिहार तक सीमित नहीं है। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और यहां तक कि लोकसभा चुनावों तक में एग्जिट पोल्स बार-बार चित्त होते आए हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में तो लगभग हर एजेंसी ने एनडीए को 350-400 सीटों का आकाश छूता अनुमान दिया था जबकि भाजपा 240 सीटों पर रुक गई थी और एनडीए 292 पर। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल्स ने 150-170 सीटों की 'महायुति' दिखा दी पर वास्तविक नतीजे 234 सीटों के विशाल बहुमत में तब्दील हो गए। झारखंड में अनुमान एनडीए का, नतीजा इंडिया ब्लॉक का बंगाल में अनुमान त्रिशंकु का, नतीजा टीएमसी की सुनामी का, तो क्या यह कहना गलत है कि एग्जिट पोल अब विश्लेषण का औजार नहीं बल्कि मनोरंजन का साधन बन चुके हैं?

सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि आखिर एग्जिट पोल्स किस 'विज्ञान' पर चलते हैं? एजेंसियां दावा करती हैं कि वे वैज्ञानिक सैम्पलिंग, पिछले चुनावों के पैटर्न, जातीय-क्षेत्रीय वितरण, बूथवार गणना और वोट शेयर रूपांतरण मॉडल पर काम करती हैं लेकिन वास्तविकता यह है कि यह डेटा कितने बूथों से लिया जाता है, कितने मतदाताओं से बात होती है, कौनसे अनुपात लागू किए जाते हैं, इन सबकी पारदर्शिता लगभग शून्य है। 'वैज्ञानिक मॉडल' की आड़ में यह उद्योग एक ब्लैक बॉक्स की तरह काम करता है, जहां अंदर क्या चल रहा है, कोई नहीं जानता और बाहर सिर्फ अनुमान बेचा जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि सैंपलिंग से नतीजे निकाले नहीं जा सकते। दुनियाभर में चुनाव पूर्व सर्वे और एग्जिट पोल आम प्रचलन में हैं लेकिन वहां मैथडोलॉजी खुली होती है, डेटा उपलब्ध होता है और एजेंसियों का मूल्यांकन उनके पिछले रिकॉर्ड के आधार पर किया जाता है। भारत में इसके उलट, टीवी चैनल टीआरपी के लिए और सर्वे एजेंसियां कॉन्ट्रैक्ट के लिए एग्जिट पोल पेश करती हैं। इन्हें वास्तविकता से ज्यादा कथानक गढ़ने में रुचि होती है। कई बार राजनीतिक पक्षधरता, कई बार व्यावसायिक दबाव और कुछ मामलों में 'सैंपल की कमी' जैसे बहाने इस उद्योग का स्थायी फॉर्मूला बन चुके हैं।

कुल मिलाकर, बिहार के 2025 के जनादेश ने एक बार फिर यह साबित किया है कि एग्जिट पोल्स मतदाता को पढ़ने का नहीं, मतदाता को प्रभावित करने का उपकरण बन चुके हैं। किसी भी लोकतंत्र में यह एक खतरनाक प्रवृत्ति है। जब टीवी चैनल और एजेंसियां मिलकर मतदाता के मन की थाह लेने के बजाय उसकी धारणाओं को दिशा देने में लग जाएं, तब उनकी विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगने स्वाभाविक है। यह समय है कि भारत में एग्जिट पोल्स के लिए स्वतंत्र विधिक नियंत्रण, स्पष्ट पद्धति प्रकटीकरण, सैम्पलिंग मानक, पारदर्शिता नियम और जवाबदेही लागू की जाए। जब तक यह उद्योग 'अनुमानों की दुकान' बना रहेगा, तब तक उसका हर अनुमान एक जोखिम होगा और उसकी हर भविष्यवाणी लोकतंत्र को भ्रमित करने का माध्यम। हालांकि बिहार ने एक बार फिर दुनिया को दिखा दिया कि यहां का मतदाता किसी भी 'पोल' से बड़ा है। 'पोल ऑफ पोल्स' विफल हुआ लेकिन जनता का पोल एकदम सही बैठा। यही बिहार की राजनीतिक चेतना की असली शक्ति है और यही लोकतंत्र की वह जीवंत धड़कन है, जिसे कोई सर्वे, कोई ग्राफ और कोई चैनल स्टूडियो कभी समझ नहीं पाएगा।

खोती मासूमियत, जिम्मेदार कौन?

अभिव्यक्ति

अदिति सिंह भदौरिया
लेखक स्तंभकार हैं।

बाल दिवस, जो कभी बच्चों की मुस्कान, खेल, और निष्कपटता का प्रतीक हुआ करता था, आज मात्र एक छुट्टी बनकर रह गया है। स्कूलों में औपचारिक कार्यक्रम, कुछ भाषण और मिठाई बाँटने तक ही इसका दायरा सीमित हो गया है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि – क्या आज के बच्चे वास्तव में 'बाल दिवस' को जी भी पा रहे हैं? क्या उनके भीतर अब भी वही मासूमियत, सादगी और निश्चल भाव शेष हैं जिनके कारण बचपन सबसे सुंदर काल कहलाता था? यदि नहीं, तो इसका दोषी कौन है ? समाज, अभिभावक, शिक्षा प्रणाली या बदलता परिवेश?

आज के बच्चों की दिनचर्या पर एक नज़र डालिए – सुबह जल्दी उठना, कोचिंग या ट्यूशन जाना, फिर स्कूल, वापस आकर होमवर्क, स्क्रीन पर घंटों बिताना, और अंत में नींद में गिर जाना। इस बीच न तो उन्हें खुलकर खेलने का अवसर मिलता है, न प्रकृति से जुड़ने का समय। उनकी दुनिया अब मोबाइल स्क्रीन, सोशल मीडिया, और डिजिटल गेम्स में सिमट चुकी है। यह 'आधुनिक बचपन' है – जहाँ खिलौनों की जगह गैजेट्स ने ले ली है और कहानियों की जगह रील्स ने।

बचपन की सबसे बड़ी पहचान होती है मासूमियत। परंतु यह मासूमियत अब तेजी से खो रही है। बच्चे आज बहुत जल्दी 'बड़े' हो रहे हैं। उन्हें चीज़ों की समझ तो है, पर संवेदनाओं का अहसास कम होता जा रहा है। वे अधिक जानकार हैं, लेकिन कम भावनात्मक। यह बदलाव केवल तकनीक या समय का परिणाम नहीं है, बल्कि हम सभी की सामूहिक जिम्मेदारी का दर्पण है।

पहला दोष समाज का है। समाज आज बच्चों से वही उम्मीदें करने लगा है जो कभी युवाओं से की जाती थीं। हर अभिभावक चाहता है कि उसका बच्चा सबसे आगे निकले, सबसे अधिक अंक लाए, हर प्रतियोगिता जीते। ऐसे में बच्चों पर बचपन से ही 'प्रदर्शन' का दबाव डाल दिया जाता है। उनके खेलने, गिरने, हँसने और सीखने की स्वाभाविक प्रक्रिया को अंक और उपलब्धियों ने निगल लिया है।

दूसरा दोष अभिभावकों का है। माता-पिता बच्चों के भविष्य को सुरक्षित बनाने की चिंता में उनके वर्तमान को ही खो देते हैं। बच्चों को खुला आकाश, स्नेह, संवाद और समय देने के बजाय उन्हें महंगे खिलौने या मोबाइल थमा दिए जाते हैं। परिवार में बातचीत का समय घटा है, और स्क्रीन टाइम बढ़ा है। भावनात्मक जुड़ाव की कमी के कारण बच्चे संवेदनहीन और आत्मकेंद्रित होते जा रहे हैं।

तीसरा दोष शिक्षा प्रणाली का है। शिक्षा आज नैतिकता और मानवता सिखाने के बजाय प्रतियोगिता और अंकों की दौड़ सिखा रही है। बाल दिवस जैसे पर्व जिनका उद्देश्य बच्चों की प्रतिभा, संवेदना और रचनात्मकता को सम्मान देना था, अब सिर्फ औपचारिकता रह गए हैं। स्कूलों में बाल दिवस पर भाषण तो होते हैं, पर बच्चों की वास्तविक भावनाओं को समझने का प्रयास कम ही किया जाता है।

चौथा कारण आधुनिक तकनीक और मीडिया है। बच्चे जिन चित्रों, गानों और वीडियो से रोज़ रूबरू होते हैं, उनमें हिंसा, दिखावा और झूठी चमक का प्रभाव अधिक होता है। मासूम मन इन्हें देखकर वैसा बनने की चाह रखने लगता है। उन्हें सरलता या सादगी आकर्षक नहीं लगती, बल्कि दिखावटी जीवनशैली अधिक मोहक प्रतीत होती है।

अब सवाल है — क्या इस स्थिति का कोई समाधान है?

हाँ, बिल्कुल है। बच्चों को फिर से मासूम, संवेदनशील और खुश बनाने के लिए हमें उनके बचपन को 'परिणाम' से नहीं बल्कि 'अनुभव' से जोड़ना होगा।

- सबसे पहले अभिभावक स्वयं बच्चों के साथ समय बिताएँ। उनकी बातें सुनें, उनके साथ खेलें, उन्हें केवल अंक और उपलब्धियों से न आँकें।
- स्कूलों को शिक्षा के साथ-साथ संवेदनात्मक विकास पर ध्यान देना चाहिए – कहानी कहने, कला, नाटक, पर्यावरण से जुड़ाव और सामाजिक कार्यों के माध्यम से बच्चों को इंसानियत सिखानी चाहिए।
- समाज को यह समझना होगा कि हर बच्चा अपने ढंग से अनोखा है। उनकी तुलना करना, उन पर दबाव डालना, उनकी मासूमियत को मारने जैसा है।
- तकनीक का सीमित उपयोग सिखाया जाए। वास्तविक खेलों, किताबों और पारिवारिक संवाद को बढ़ावा दिया जाए।

अगर हम चाहते हैं कि आने वाली पीढ़ी संवेदनशील, सच्ची और दयालु बने, तो हमें पहले उन्हें उनका खोया बचपन लौटाना होगा। वरना आने वाले वर्षों में बाल दिवस सिर्फ कैलेंडर की तारीख बनकर रह जाएगा और हम सब इस मासूमियत के खोने के जिम्मेदार कहलाएँगे।

स्वामी, सुबह सवेरे मीडिया एल.एल.पी. के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक उमेश त्रिवेदी द्वारा श्री सिद्धीविनायक प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 26-बी, देशबंधु परिसर, प्रेस कॉम्पलेक्स, जोन-1, एम.पी.नगर, भोपाल, म.प्र. से मुद्रित एवं डी-100/46, शिवाजी नगर भोपाल से प्रकाशित।

प्रधान संपादक
उमेश त्रिवेदी
कार्यकारी प्रधान संपादक
अजय बोकिल
संपादक (मध्यप्रदेश)
विनोद तिवारी
वरिष्ठ संपादक
पंकज शुक्ला
प्रबंध संपादक
अरुण पटेल
(सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल रहेगा)
RNI No. MPHIN/ 2003/ 10923,
Ph. No. 0755-2422692, 4059111
Email- subahsaverenews@gmail.com

'सुबह सवेरे' में प्रकाशित विचार लेखकों के निजी मत हैं। इनसे समाचार पत्र का सहमत होना आवश्यक नहीं है।

व्यंग्य

केदार शर्मा

लोभ और भय का मकड़जाल

साइबर अपराधी मृत्यु के बाद यमलोक पहुँचा। यमराज ने क्रोध से घूरते हुए कहा-अरे अधम! तूने धरती पर लोगों को जाल में फंसा कर उनका धन लूटा है। तेरे लिए तो नरक की यातना तय है।

साइबर अपराधी हाथ जोड़कर बोला-हे महाराज, आप न्याय के देवता हैं। कम-से-कम अपनी बात कहने का मौका तो मुझे दीजिए। वहाँ हमारी धरती पर तो मेरी सजा के खिलाफ मैंने अंतिम अदालत तक में केस लड़ा था। अंतिम फैसला आने से पहले ही बूढ़ा होकर मृत्यु को प्राप्त हो गया हूँ। आपकी तो उससे भी ऊँची अदालत है। आप बिना सुनवाई के ही मुझे यातनागृह के लिए फारवर्ड कर रहे हैं!

यमराज को बात में तर्क दिखाई दिया। बोले–' ठीक है, कहो क्या कहना चाहते हो?

अपराधी ने कहना शुरू किया-हे यमराज जी, आदमी अपने भीतर छुपे लोभ और भय के भूत से डरकर स्वयं ही मकड़जाल में फँसता है। संसार में सर्वत्र डर एवं लोभ से काम हो रहा है। तुलसीदास जी ने मानस में कहा है - काम क्रोध मद लोभ सब, नाथ नरक के पंथ। यानि नरक यातना के लिए लोभी भी काबिल हैं। लोभ पाप का जनक कहा गया है, तो भय मन का भूत। अगर यह दोनों खोट मनुष्य में नहीं हो तो वह साइबर अपराधी के 'जनक के जनक' से भी नहीं फँस सकता है।

हे यमराज जी, मनुष्य भय और लोभ ये दोनों बातें बचपन से ही सीखना शुरू कर देता है। लॉलीपॉप का लोभ दिखाकर मुझसे भी बचपन में बहुत से काम करवाए गए। वहीं भूत का भय दिखाकर अपनी बातें मनवाई गई।

थोड़ा बड़ा हुआ तो दुनिया में हर कहीं मुझे लोभ और डर का ही नेटवर्क फैला मिला। लोग कांटे में आटा लगाकर मछलियाँ फँसाते मिले। फैल होने के डर और नौकरी के लोभ से किताबे पढ़ते मिले।

किताबें तो नैतिक कर्तव्य और नैतिक आचरण की बातों से भरी मिली। दूसरी ओर असल जिंदगी में लोभ और भय का लाइव डेमो चलता मिला। जिस दिन दफ्तर में अफसर छाती पर खड़ा हो उस दिन काम फास्ट मोड पर रन करता मिला और जिस दिन वह बोस छुट्टी पर हो उस दिन स्लो मोड पर या हैंग मिला। सुविधा शुल्क मिलते ही फाइलें हाई स्पीड इंटरनेट सी दौड़ने लगी। जहाँ नोटिस और चार्ज शीट मिलने की आशंका हुई, वह काम अलर्ट मोड पर आ गया और जिसमें कोई फर्क न पड़े सिवाय आम आदमी के, वह लाल बस्ते में बंध गया। कहते-कहते साइबर अपराधी का गला भर आया।

उसने रुंधे गले से आगे बताया–-''हे यमराज जी, वह मेरे कारण नहीं बल्कि अपनी ही भययुक्त दुर्बलता के कारण डिजिटल अरेस्ट हो जाता है। अपने परिजनों के फँसने का डर से, जो भले ही झूठा हो, बंदा डर जाता है।

मुफ्त की राशि खाते में आने पर ओ.टी.पी. मेरे कारण नहीं अपने लोभ के वशीभूत हो राजी-राजी बता देता है ।फिर चाहे खाता खाली हो या मोबाइल हैक। आदमी यह भी नहीं सोचता कि आखिर मुफ्त में कौन किसी को देता है? यह है भय और लोभ का मकड़जाल, जिसमें साइबर अपराधी हो रहे मालामाल।

शादियों का सीजन शुरू हो गया है। सुना है- निमंत्रण पत्र पाने की चाह या किसी अज्ञात सुंदरी के दर्शन और संवाद के लोभ के वशीभूत हो कई बंदे बिना सोचे समझे अपने पासवर्ड शेयर करने को अपना कर्तव्य समझते हैं।

सो हे यमराज जी, मैंने तो जाल बिछाकर परीक्षा ली है और भीतर छुपे इनके पापों को आईना दिखाकर उजागर ही किया है। मुझे सजा देना और उनको छोड़ना न्यायोचित नहीं है। न्याय सबके लिए बराबर होना चाहिए।

साइबर अपराधी की तर्कसंगत बातें सुनकर यमराज सोच में पड़ गए और अपने दूतों से बोले-ठीक है, धरती पर कहीं न कहीं सिस्टम एरर तो है। इस विचाराधीन कोठरी में रखो। इसका केस पेंडिंग ही रखो।

... और क्या कह रही है ज़िंदगी

ममता तिवारी

लेखक साहित्यकार हैं।

बच्चे घर आ रहे हैं और जिंदगी धड़क उठी है

फिर बचपन शब्द के साथ एक शब्द कुदरतन जुड़ा है 'माँ'। माँ की यादों के बिना यह डायरी अधूरी है। 'मां' का बचपन कभी खत्म नहीं होता, बच्चों की यादों के साथ उसका मन बचपन के गलियारे में घूमता रहता है। पैदा करती, पालती, स्कूल भेजती, इंतजार करती, दूर देष में रहते बेटे बेटी को याद करती, मां जब-तब इन यादों की फिसलपटिट्यों पर बैठ फिसलने लग जाती है।

पलंग के नीचे से
इक पुराना बक्सा खींचती हूँ
खोल के इक-इक याद सहेजती हूँ
नापसबंद कर देती हूँ
ताकि यादें कहीं घर में न बिखर जायें
तुम्हारे खिलौनों की तरह...। (यादों की फिसल पट्टियाँ)

पहले हमारे लिए दशहरा दीवाली, होली, ईद क्रिसमस वगैरह जैसे खास त्यौहार आते थे। आज हमारे लिए सबसे बड़ा त्यौहार हो गया है, 'बच्चों का घर आना'। अगर मैं अपनी ही कॉलोनी का स्टेट्स बताऊँ तो लगभग 80 प्रतिशत माता पिता अकेले रह रहे है बच्चों का आगमन उनके जीवन में खुशहाली लाता है। हिंदुस्तान की बात नहीं कर रही। ये वो बच्चे हैं जो या तो विदेश में पढ़ रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं या वहीं सैटल हैं। कॉलोनी में शाम को जब सब महिलायें एकत्र होती हैं तो अपनी खुशी ज़ाहिर करती हैं, पुरूष अपनी भावनायें छुपा कर दोस्तों में कहते हैं, हाँ, बेटा/बेटी आ रही है श्रीमती जी अब व्यस्त हो जायेगी। आंसू छलक जाते हैं। उनकी आलमारियां साफ हो रही हैं। व्यंजनों की लिस्ट बन रही है। रजाइयाँ धूप का जाने का इंतज़ार कर रहा है। घर के बड़ों ने कहा था इतनी दूर मत भेजों पर उसने कहा था-

मुझे एक अवसर तो दो
मैं उड़ना चाहता हूँ
भले ही पंख छोटे हैं अभी मेरे,
शायद मैं गिर भी जाऊँ
पर, मैं गिर के उठना चाहता हूँ।
मुझे एक अवसर तो दो,
मैं दुनिया देखना चाहता हूँ
भले ही आँखें अभी अनुभवहीन है मेरी
पर तुम्हारी अनुभवी आँखों का भागीदार बन
अपने अनुभवों को दो गुना करना चाहता हूँ।
मुझे एक अवसर तो दो
मैं कुछ नया करना चाहता हूँ
भले ही डगर अनजान हो मेरे लिये,
और तुम्हारे बनाये फूलों के रास्ते ना हो,
पर संघर्ष के काँटों से रूबरू होना चाहता हूँ।
मुझे एक अवसर तो दो,
मैं ज़िम्मेदारियाँ उठाना चाहता हूँ।
भले ही खिलदंडा, मनमौजी अलमस्त हूँ
पर तुम्हारी तरह काम को बोझ की तरह लिये बिना,
ज़िन्दगी की कड़वाहट को मिठास समझ,
घूँट-घूँट पीना चाहता हूँ।
मुझे एक अवसर तो दो,
मैं जुझारू बनना चाहता हूँ,
भले ही कभी दुर्गम पथ पर
पैर ना रखा हो मैंने।
पर तुम्हारे कोमल पंखों की गराहट से निकलकर
रोज़मर्रा की आपाधापी से जूझना चाहता हूँ।
मुझे एक अवसर तो दो,
'मैं' 'मैं' होना चाहता हूँ
भले ही नाम की तख्ती,
मेरे जीवन पर तुम्हारी लगी रहे,
पर उस नाम को सिर आँखों पर लिये,
मैं अपना वजूद पाना चाहता हूँ। (उड़ान)

अब सिवाय उसका कमरा संवारने के पुराने एलबम तस्वीरें देखने के कुछ भी तो नहीं रहा। शाम से मोबाइल देखना शुरू हो जाता है मांओ का (वैसे भी पिता से ज़्यादा माँ के पास फोन आता है पिता कान लगा के सुनने की कोशिश करते है) फिर जैसे हम को कुछ फर्क नहीं पड़ता के अंदाज़ में पूछते है ठीक तो है, पैसे तो नहीं चाहिए।

वहाँ मेरे बनाये दाल-चावल याद करते हो,
यहाँ गैस पर चढ़ी मेरी दाल जल जाती है।
मैं नहीं चाहती आये तुम्हारी याद ज़्यादा तो,
रसोई में आज कल कम जाती हूँ...
तुम्हारी कोई शर्ट हाथ आते ही
उसे धोने का सोचती हूँ

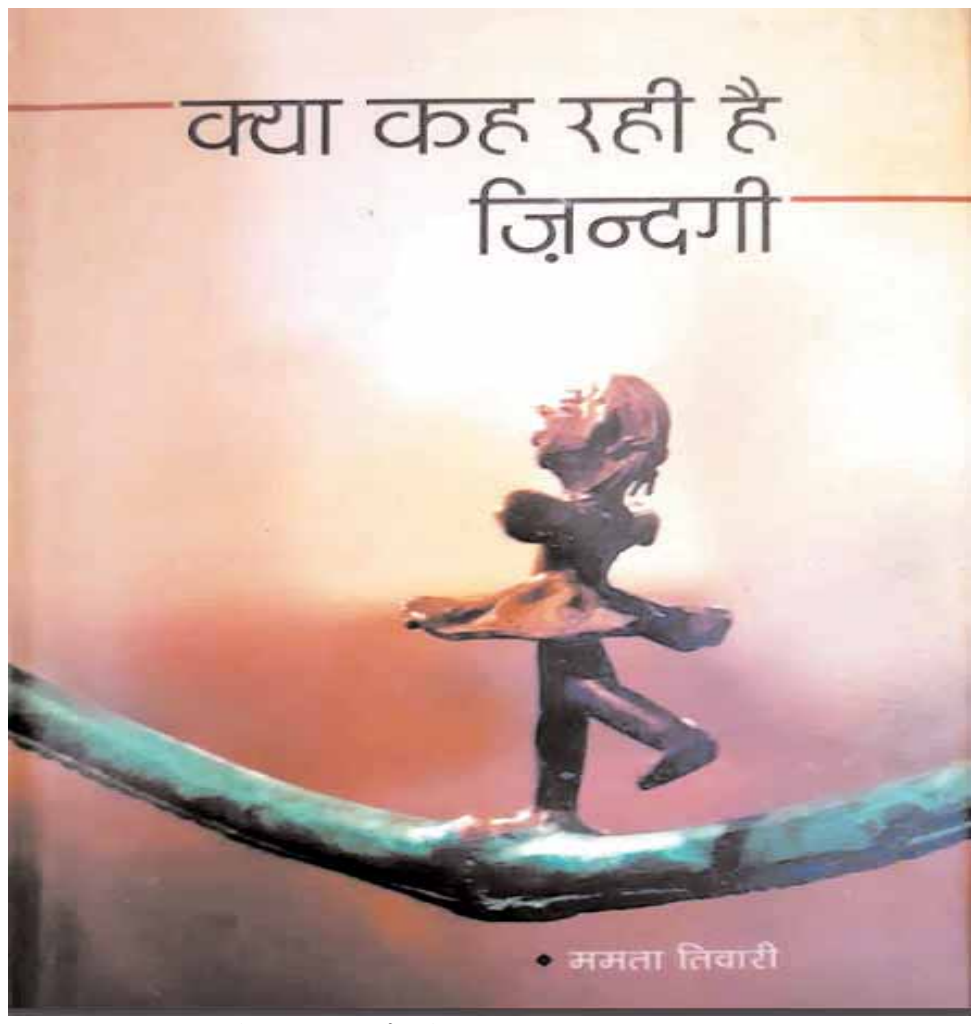

पर तुम्हारी महक न मिट जाये कहीं
इसलिये झट फिर सहेज लेती हूँ....
छोटे के बालों में तेल लगाते वक़्त
तुम्हारा रूखा चेहरा याद आता है
खाने बैठती हूँ, तो चटपटे आलू देख
निवाला अटक जाता है
सोचो, तेल, मिर्च, मसालों में
इस कदर बसे हो तुम तो,
ज़िंदगी में किस शिद्दत से घुले होंगे?
(दूर देश में तुम)

एक बात ज़रूर अच्छी हो गई है कि हमारे सिखाये संस्कारों की वो बहुत अच्छे से कदर कर रहे हैं। भारत में होते थे तो लगता था भगवान को प्रणाम भी करेंगे या नहीं। अब हर त्यौहार की महत्ता उन्हें समझ आ रही है। पुरानी दीवाली होली के किस्से याद करके बताते हो, कब गन्ना आता है, कब अमरूद, होली, आ रही है सब याद रहता है उन्हें। पूछ-पूछ कर पूजा त्यौहार मनाते हो भारत में पारंपरिक कपड़े मंगवाते हो जिस गुझिया की तरफ देखते भी नहीं थे उसे शौक से बनवा के खाते हो। जानते है उन मांओ के दिलों का हाल जो एयरपोर्ट, स्टेशनों पर खड़े हो बच्चों का इंतज़ार करती है उनका दिल कानों में उछल कर बजता है उतरते हो देखते है या हाय राम खाना नहीं मिलता क्या कितने दुबले हो गये हो। उफ़्फ नज़र ना लगे कितना बड़ा/बड़ी हो गए। मन ही मन नज़र से बचाने को (थू-थू) करती है। एकदम से गले लगाते थोड़ी झिझक होती है

अब तुम बड़े हो गये हो
मेरी बाँहों में नहीं समाते
ना ही डरने पर, अब रातों को जगाते,
बारीक सी डोर से बँधे हैं हम,
नाभि के संबंध
यूँ आसानी से नहीं डगमगाते।।
अब तुम बड़े हो गये हो...
मेरी धुंधली आँखों में
ख़्वाब सिर्फ़ तुम्हारे ही आते
टपने सफ़ेद बालों को गिन
जोड़ती हूँ तुम्हारी उम्र
पर उँगलियों पर अब अंक
भी नहीं समाते।
मैं जानती हूँ
अब तुम बड़े हो गये हो.....
पर जाने क्यों अब भी
आँगन में नन्हें पैरों से भागते नज़र आते।
चीरने चले हो आसमाँ का सीना
पर मुझे तो सदा झूले में ही खिलखिलाते नज़र आते।
तुम्हारी नज़रों से देखना चाहती हूँ दुनिया को
मेरी आँखों में तो
अब कोई नज़ारे नहीं आते
आकाष के तारे छूने चले हो
पर, मेरे मन के गगन पर
सदा तुम 'मधुर'-'मधुर' मुस्कुराते। (अब तुम बड़े हो गये हो)

चूंकि वो डायटिंग पे है तो आप दुःखी भी है कि अब क्या बनाऊँगी आखिर उनका व्रत तुड़वा ही देती है और उनका मनपसंद नाश्ता बना कर उनसे पूछती और क्या कह रही है जिंदगी?

नर्मदा के आँसू उसी के पानी में, किसी को दिखाई नहीं दे रहे हैं

राजेन्द्र जोशी

स्वतंत्र पत्रकार

नर्मदा नदी की दुर्दशा काल सत्तर के दशक से प्रारम्भ गया था जब विकास की कल्पना के साथ नर्मदा नदी पर बांध बनने का सिलसिला आरंभ हुआ जो आज तक जारी है,बांधो ने जहां नदी की धार को थाम लिया तो मामूली मुआवजे के दम पर किसानों की नदी के किनारों की सेकड़ों एकड़ बेशकीमती जमीने बांधों ने लील ली, बाद उसके बजरी माफ़ियाओं ने नदी के दोनों किनारो को छलनी कर दिया जो आज भी अत्याधुनिक मशीनों ओर बाहुबल के दम पर जारी है,जबकि बांध प्रभावित इलाको मे इस पर रोक लगाई गई है,हाल ही में नर्मदा से 5 किमी क्षेत्र की वन व राजस्व भूमि खनिज कंपनियों को लीज पर दी जाने लगी है,पड़ताल में दो जिलो खण्डवा और धार जिलो की जमीन खनिज खनन हेतु दिये जाने के पत्र सामने आये है तो विरोध के स्वर भी सुनाई देने लगे है ।

ताजा घटना क्रम मे जो तथ्य सामने आये है उनमें खंडवा जिले मे स्थित ओंकरेश्वर ज्योतिर्लिंग से लगभग 01 किमी की दूरी पर स्थित 699 हैक्टर मे फेले मोहदरी वन की जमीन को फास्फोराइड ब्लॉक के लिए गुरुग्राम की कमोडिटी हब कम्पनी को लीज पर दे दिया गया है,दूसरी ओर धार जिले की कुक्षी तहसील के चार ग्राम टकारी,तलवाड़ी एव घोडा(ईस्ट ऑफ डाब्ररी लाईम स्टोन ब्लॉक) हेतु रकबा 815 हैक्टर ओर ग्राम बामनवर्डी (बामनवर्डी लाईम स्टोन खनिज क्षेत्र का विवरण ब्लॉक) का रकबा 913 हैक्टर क्षेत्र 03 वर्ष खनिज व चुना पत्थर हेतु 03 वर्ष के के लिए मेसर्स श्री सीमेंट लिमिटेड ब्यावर राजस्थान को आलाट किया गया है।

मप्र के प्रधान वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख वन विभाग भोपाल ने पत्र कर्मांक 4675 दिनांक 07/11/2025 के द्वारा नर्मदा नदी से लगे हुये जिलो व नगरो अनुपपुर,खंडवा,खरगोन,बडवाह, बड़वानी,धार, अलीराजपुर, हरदा, जबलपुर पूर्व मंडला,पश्चिम मंडला,डिडोरी, देवास, नरसिंहपुर, उत्तरसिवनी, सिहोर, नोरादेवी के वनमडलाधिकारियों को निर्देशित किया की नर्मदा नदी के किनारों के 5-5 किमी परिधि की वन भूमि ओर वन कक्षों को अतिक्रमण से मुक्त करवाए।

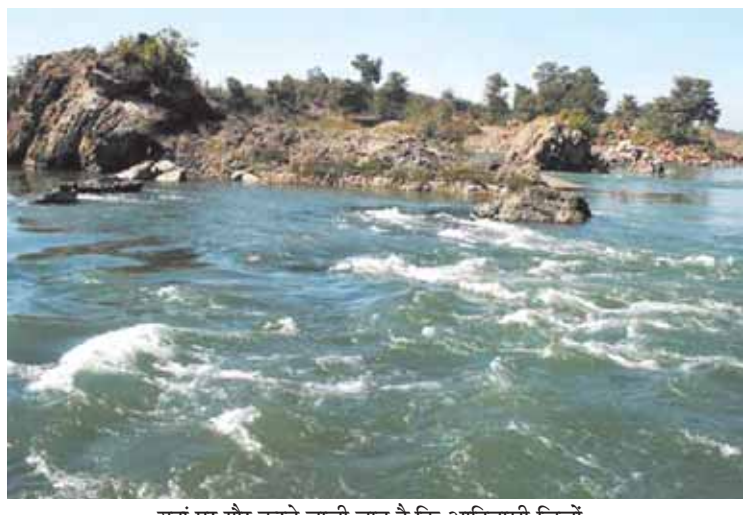

यहां पर गौर करने बाली बात है कि आदिवासी जिलों में आदिकाल से आदिवासी और मानकर समाज पीढ़ी दर पीढ़ी नर्मदा नदी के तटीय क्षेत्र और पहाड़ों की भूमि पर काबिज है,वन विभाग के ताजा आदेश से उनके रहने व आजीविका पर संकट के बादल नजर आने लगे है।

यह सर्वविदित है है की नर्मदा घाटी खनिज संपदा से परिपूर्ण होने के साथ ही मानव विकास की सभ्यता से जुड़े कई प्रमाण भी समय समय पर मिले है,नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के द्वारा अस्सी नब्बे के दशक मे पुरातत्व विभाग के विशेषज्ञो के माध्यम से नर्मदा घाटी मे करवाई गईं खुदाई में आदि पाषाण काल की मानव सभ्यता से जुड़े अवशेष मिले थे,वह खनन भी जल्द बंद कर दिया गया,सुनते आ रहें है कि, नर्मदा घाटी मे 92 टीले खनन हेतु चिन्हित किए गए थे अगर सभी की खुदाई होती तो सरदार सरोवर बांध का कार्य प्रभावित हो सकता था।

वर्तमान में नर्मदा के तटीय क्षेत्रों मे खनिज संपदा हेतु आवंटित जमीन के विरोध में बडवाह नगर के सामाजिक ओर धार्मिक व्यक्तियों के समूह ने मप्र हाईकोर्ट मे याचिका दायर की है,जबकि अलीराजपुर जिले के ग्राम दाबडी में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष,नेता प्रतिपक्ष जोबट कुक्षी के विधायक,अलीराजपुर के पूर्व विधायकों के द्वारा नर्मदा किनारे की 5 एकड़ वन भूमि के अधिग्रहण को लेकर विरोध सभा का आयोजन किया जिसमें हजारों आदिवासी शामिल हुये।

गौरतालब है की मध्यप्रदेश विधान सभा भी मई 2017 में ध्वनिमत से पारित एक अशासकीय संकल्प में नर्मदा को कानूनी जीवित इकाई मान चुकी है,साथ ही साथ प्रदेश के कई प्रमुख राजनेता नर्मदा परिकृमा कर चुके है,लेकिन आज तक उनकी इस बाबद कोई प्रतिक्रया सामने नही आई है।

प्रकृति प्रदत्त नदियों पर भी भक्तो की श्रेणीया विभाजित होने लगी है,हर व्यक्ति,समाज यह बताना चाहता है की वह ही सबसे बड़ा भक्त है है,इसी संदर्भ मे हम मप्र की जीवन दायनी नर्मदा नदी को देखते है तो विगत सालो की मुक़ाबले नर्मदा भक्तों की संख्या ओर श्रेणियों में काफी बढ़ोत्तरी हुई है, एक तरह से यह आस्था-श्रद्धा से इत्तर सामाजिक राजनीतिक धार्मिक हेसियत के अनुसार भक्ति दिखाई पड़ रही है, नर्मदा नदी के दोनों किनारो पर सालों से खनिज माफ़िया की निगाहे थी ओर कई तथाकथित खनिज माफ़ियाओ ओर उनके गुर्गों ने पुण्य के साथ व्यवसाय की नर्मदा परिकृमा का लाभ लिया होगा इससे इंकार नहीं किया जा सकता,जबकि जिसके लिए यह परिक्रमा चल रही हे ,उसके आँसू उसी के पानी में किसी को दिखाई नहीं दे रहे है।

दृष्टिकोण

ब्रजेश कानूनगो

लेखक साहित्यकार हैं।

आरपार की बात

एक होता है समदर्शी और एक होता है पारदर्शी। बड़े कमाल के होते हैं ये दोनों शब्द। समदर्शी तो एक मायने में ठीक ही लगता है, सबको एक निगाह से देखना और एक लाठी से हांक देना जैसी फिजूल बातों को यदि छोड़ दें तो यह एक बेहतरीन विचार है। समानता हर धर्म और मत का सपना रहा है। किसी मानवीय विचारधारा के लिए बेहतर इंसानी समाज बनाने का उद्देश्य रहा है, मगर कई बार पारदर्शी शब्द पर गहरे जाकर सोचने का मन करता है। जब भी कोई घोटाला उजागर होता है अपने बचाव में आरोपी पक्ष कहता है –हमने तो सम्पूर्ण पारदर्शिता बरती थी। लेकिन घोटाला हो गया है। घोटाले के दैत्य पर पारदर्शिता के सुकोमल शब्द–पंख चिपका कर पूरे प्रकरण को अक्सर मनोहारी परिंदे का रूप देकर उड़ा देने के प्रयास होने लगते हैं।

कुछ बातें समझने के लिए कोई दार्शनिक होने की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही दर्शन का कोई अध्येता होने की। खुद को एक दृष्टा समझने के बजाय सिर्फ दर्शक समझ कर चुपचाप दर्शन में लगे रहा जाए यानि किसी संदर्भ को देखना, निहारना, टापते रहना तो उसके बारे में कई बार बेहतर समझना संभव हो जाता है। जरूर बस इस बात की है कि जब कहीं कोई अवांछित बात देखी जाए तो उस पर गौर किया जाए। यूं भी आजकल बहुत सारी ऐसी बातें सामने घट रही हैं जिनमें बाल की खाल उधेड़ना न केवल अमूर्त सुख देता है बल्कि उससे कई नए आयाम भी निकल आ सकते हैं। हालांकि बाल की खाल उतारने वाले कई लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो अपने भोजन में धोखे से गिरे बाल को देख लें तो चुपचाप उसे हटा देते हैं, लेकिन किन्ही सहज दिखने वाली बातों पर भी सवाल करके उसके वास्तविक अर्थ निकाल लाते हैं, मतलब किसी के सुंदर और सौम्य दिखने वाले चेहरे के पीछे उसका विकृत मन भी छिपा हो सकता है। सौंदर्यबोध की पारंपरिक परिभाषा में कुछ धारणाएं ठहरी हुई हैं मगर जब आधुनिक सौंदर्य बोध में भी कोई प्रश्न नहीं दिखता तो अफसोस होता है।

एक होता है समदर्शी और एक होता है पारदर्शी। बड़े कमाल के होते हैं ये दोनों शब्द। समदर्शी तो एक मायने में ठीक ही लगता है, सबको एक निगाह से देखना और एक लाठी से हांक देना जैसी फिजूल बातों को यदि छोड़ दें तो यह एक बेहतरीन विचार है। समानता हर धर्म और मत का सपना रहा है। किसी मानवीय विचारधारा के लिए बेहतर इंसानी समाज बनाने का उद्देश्य रहा है, मगर कई बार पारदर्शी शब्द पर गहरे जाकर सोचने का मन करता है। जब भी कोई घोटाला उजागर होता है अपने बचाव में आरोपी पक्ष कहता है -हमने तो सम्पूर्ण पारदर्शिता बरती थी। लेकिन घोटाला हो गया है। घोटाले के दैत्य पर पारदर्शिता के सुकोमल शब्द-पंख चिपका कर पूरे प्रकरण को अक्सर मनोहारी परिंदे का रूप देकर उड़ा देने के प्रयास होने लगते हैं।

पारदर्शिता का यह नया मुहावरा इन दिनों बहुतायत से चलन में है।व्यक्ति हो, प्रशासन हो या नीति या प्रक्रिया अपनाने की बात हो, हर कहीं पारदर्शिता की फिटकरी घुमाकर गन्दगी का तलछट हटाने की कोशिश की जाने लगती है। आदमी भले ही बेईमान हो लेकिन उसका व्यक्तित्व पारदर्शी कहा जाता है, ऐसी प्रक्रिया भले ही अपनाई गई हो जिससे देश के राजस्व को चूना लगा हो लेकिन उसे सौ प्रतिशत पारदर्शी सिद्ध करने की कोशिश की जाने लगती है।

आखिर यह पारदर्शी क्या है? शाब्दिक रूप से समझा जाए तो ऐसी चीज जिसके आर-पार देखा जा सके, जैसे कांच होता है, ठहरा हुआ जल होता है, चश्मे का लेंस होता है। पारदर्शी व्यक्तित्व के अन्दर और उसकी पीठ के पीछे जो कुछ छुपा हुआ हो स्पष्ट नजर आ सकता है,वह छुपा नही रह सकता,बल्कि देखा जा सकता है। कहने का मतलब यह भी हुआ कि जो बातें बाहर से दिख रही है वही अंदर भी हैं, यह नहीं कि कहने को कुछ हो और करने के स्तर पर चल रहा हो वह कुछ और हो।

प्रश्न यह उठता है कि अगर किसी व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व पारदर्शी है तो क्या वह इतना पारदर्शी हो सकता है कि अपने अन्दर होने वाली या उसकी आड लेकर की जानेवाली सारी बेइमानियों को स्पष्ट नजर आने देगा ?

क्या उसमे इतनी पारदर्शिता बनी रह सकेगी या वह स्वार्थ की धुन्ध से अपनी असली पहचान को ही ओझल बना कर लोगों को भ्रमित करने की चेष्टा करेगा ? यह भी हो सकता है कि उसकी पारदर्शिता किसी लेंस की तरह हो जो वास्तविकताओं को छोटा या बडा अथवा विकृत बना कर प्रस्तुत कर दे। विज्ञान और तकनीकी की दुनिया के विस्तार के साथ-साथ ऐसा लगता है कि पारदर्शिता के संसार में भी कुछ नए प्रयोग चल रहे हैं, जिसमें कई बार आरपार एक समान दिखने वाले दृश्य भी कई स्तरों पर कुछ और ही संदर्भ लिए होते हैं।

कई राज्यों के दावे रहते हैं कि उनकी सरकार और उनका प्रशासन जनता को पारदर्शिता उपलब्ध कराने को प्राथमिकता दे रहा है। यह सुखद लगता है कि प्रशासन पारदर्शी हो। प्रशासन की मशीन मे होने वाले भ्रष्टाचार और उसमे व्याप्त गन्दगियां नागरिकों को स्पष्ट नजर आ सकें। आम आदमी देख सके कि अपना काम करवाने के लिए कहाँ और कितनी भेंट चढानी पढ़ रही है, कहाँ और किसकी एप्रोच से काम बन सकता है। पारदर्शिता के कारण डीलिंग के सूत्र और गलियारे खोजने मे आसानी हो सकती है। पारदर्शी प्रशासन मे सब कुछ साफ साफ नजर आ सकेगा कि किस लीडर को साधने से उत्पादक क्षेत्र मे स्थानांतर करवाया जा सकता है। प्रशासन के किस पेंच मे तेल डालकर प्रशासनिक घर्षण को कम किया जा सकता है। प्रशासन का पारदर्शी होना अधनंगे सुखिया से लेकर करोडपति सेठ सुखनन्दन तक के लिए हितकारी है। इसमें फर्क कैसे किया जा सकेगा कि दोनों के हित के संदर्भ में इंसाफ और औचित्य किस पक्ष में खड़ा है। इसे समझिए श्रीमान!

मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य में लगे नपा के 17 सहायक निरीक्षकों की ड्यूटी

एआईआर की ड्यूटी से राजस्व वसूली पर लगा ब्रेक, नपा में गहरा सकता है वित्तीय संकट

एस. द्विवेदी, बैतूल। नगरपालिका की आर्थिक हालत पहले से ही ठीक नहीं है। पिछले तीन महीनों से कर्मचारियों का वेतन निकालने के लिए नगरपालिका को संघर्ष करना पड़ रहा है। वही दूसरी तरफ भारत निर्वाचन आयोग ने 4 नवंबर से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत नगरपालिका के 17 सहायक राजस्व निरीक्षकों की ड्यूटी जिला निर्वाचन कार्यालय ने 4 दिसंबर तक बीएलओ के सहायक के रूप में लगा दी है। इन निरीक्षकों को मतदाता सूची में सुधार और नए नाम जोडने के कार्य के लिए घर-घर जाना पड़ रहा है। कई निरीक्षकों को एक से अधिक वार्डों में बीएलओ के साथ जिम्मेदारी दी गई है, जिससे उनका पूरा समय चुनावी कार्य में ही लग रहा है। परिणामस्वरूप, राजस्व वसूली का काम पूरी तरह ठप हो गया है। बता दे कि नगरपालिका की कमजोर वित्तीय स्थिति को सुधारने हाल ही में वसूली अभियान की शुरुआत की गई थी। सीएमओ ने सभी सहायक राजस्व निरीक्षकों को वसूली के लक्ष्य दिए थे और प्रतिदिन इसकी समीक्षा की जा रही थी। उद्देश्य यह था कि नगर के राजस्व में बढ़ोतरी हो सके और कर्मचारियों के वेतन सहित जरूरी खर्चों का समय पर भुगतान किया जा सके, लेकिन सहायक राजस्व निरीक्षकों की बीएलओ के सहायक के रूप में ड्यूटी लगने से नपा के राजस्व वसूली कार्य प्रभावित हो रहा है।

हर माह करना पड़ता है लाखों का वेतन भुगतान

बताया गया है कि नगरपालिका पर हर महीने लाखों रूपये का वेतन भुगतान करना पड़ता है। दूसरी ओर, शहरवासियों पर लगभग 11.50 करोड़ रुपए का टैक्स बकाया है। इस राशि में से अब तक केवल 30 प्रतिशत वसूली ही की जा सकी है। राजस्व वसूली की कमजोर स्थिति को देखते हुए नगरीय प्रशासन विभाग ने कुछ सप्ताह पहले ही सभी निकायों को वसूली सख्ती से करने के निर्देश दिए थे। बैतूल नगरपालिका ने भी इन निर्देशों पर अमल शुरू किया था। सीएमओ ने सभी कर्मचारियों को वसूली के लिए वार्डवार लक्ष्य सौंपे थे और प्रतिदिन रिपोर्ट मांगी जा रही थी।

निर्वाचन कार्य के चलते वसूली अभियान धीमा

नपा सीएमओ के निर्देश के बाद सहायक राजस्व निरीक्षकों ने राजस्व वसूली को लेकर अभियान तेज कर दिया था। प्रतिदिन कुछ न कुछ राजस्व वसूली भी आ रही थी। कुछ जगहों पर तो कर्मचारियों ने बकायेदारों को नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन अब निर्वाचन कार्य के चलते पूरा अभियान थम गया है। नगरपालिका के एक अधिकारी ने बताया कि चुनावी कार्य खत्म होने के बाद ही वसूली दोबारा शुरू की जा सकेगी। मगर तब तक काफी समय बीत जाएगा और राजस्व स्थिति और कमजोर हो जाएगी। अधिकारी का कहना है कि वसूली अमले को चुनावी कार्य में लगाना मजबूरी है, क्योंकि यह आदेश निर्वाचन कार्यालय से आया है।

संभावित संकट, वेतन देना भी मुश्किल होगा

जानकारों का कहना है कि यह स्थिति नगरपालिका के लिए बड़ी परेशानी बन सकती है। अगर नवंबर और दिसंबर में वसूली नहीं हो पाई, तो आने वाले महीनों में कर्मचारियों को समय पर वेतन देना भी मुश्किल हो जाएगा। सफाई, प्रकाश व्यवस्था, जल आपूर्ति और छोटे विकास कार्यों पर भी असर पड़ सकता है। नगर प्रशासन के अनुसार, फिलहाल स्थिति पर नजर रखी जा रही है। लेकिन नगरपालिका के पास फिलहाल न कोई वैकल्पिक आय का स्रोत है और न ही अतिरिक्त फंड की संभावना दिख रही है। कुल मिलाकर, बैतूल नगरपालिका की वित्तीय हालत पहले से ही संकट में है और अब निर्वाचन कार्य की वजह से राजस्व वसूली की रफ्तार और धीमी हो गई है।

इनका कहना है -

निर्वाचन कार्यालय के निर्देश पर 17 एआईआर की ड्यूटी बीएलओ के साथ लगाई है। करीब एक महीने तक एआईआर को बीएलओ के साथ ही निर्वाचन का कार्य करना होगा। इससे वसूली का काम तो प्रभावित होगा, मगर कर क्या सकते हैं।

- सतीश मटसेनिया,
सीएमओ नगरपालिका बैतूल

जनजातीय गौरव दिवस

मंत्री और विधायक दोनों आदिवासी फिर भी सम्मान से अछूती लाडो

बैतूल। एमपी बोर्ड की कक्षा 10वीं में घोड़ाडोंगरी ब्लाक के चिखलीमाल गांव के स्कूल की छात्रा शिवानी कवडे ने स्कूल में टॉप किया। उसने कक्षा दसवीं में 82. 2 प्रतिशत अंक प्राप्त किए थे। शिवानी के स्कूल में टॉप करने के साथ ही तीन खास बात थी, जिसमें पहला उसके माता-पिता दोनों निरक्षर होना थी।कहते हैं कि माता-पिता हर बच्चे के पहले गुरु होते हैं ।दूसरा नंबर शिक्षक का आता है, लेकिन जब माता-पिता ही निरक्षर हो और कभी स्कूल की दहलीज पर पाव ना रखें हो तो बच्चों की पढ़ाई का क्या होगा? यह एक सवाल दिमाग मे कौंधता है, लेकिन इसका जवाब टॉपर, हो तो जीभ दांतों के बीच आ जाती है। दूसरी खास बात इस स्कूल में 2019 के बाद पहला मौका था जब स्कूल का रिजल्ट 86.37 प्रतिशत तक पहुंचा था और तीसरी उपलब्धि ये थी कि पिछले 6 सालों के दौरान ये भी पहली बार हुआ, जब एक आदिवासी वर्ग की बालिका ने स्कूल में टॉप किया। स्कूल की आदिवासी बालिका को इस उपलब्धि से खुश होकर इसी स्कूल से रिटायर हुए प्रभारी प्रिंसिपल आनंद साहू ने इस बालिका को 5000 की राशि भेंट की लेकिन इस आदिवासी बालिका का अब तक किसी मंच पर सम्मान नहीं हो सका। जबकि बैतूल जिले की घोलडोंगरी विधानसभा सीट से महिला आदिवासी विधायक है। बैतूल -हरदा, हरसूद सीट से सांसद व केंद्रीय मंत्री भी स्वयं आदिवासी वर्ग से आते हैं, लेकिन इसमें बावजूद भी शिवानी जैसी बेटी से मिलने उनके घर तक कोई नहीं पहुंचा। यहां तक आदिवासी आबा की जयंती को जनजातीय समुदाय के गौरव दिवस मनाया गया लेकिन समाज के इस लाड़ली के गौरव को भी भूल गए। जबकि जिले की कई प्रतिभाओं को बैतूल में बड़े-बड़े आयोजन कर सम्मनित किया गया था।

कलेक्टर बनने का सपना

शिवानी कवड़े के माता-पिता ने मजदूरी कर गरीब परिस्थित में बेटी को पढ़ाया। बेटी ने भी उनकी मेहनत को अच्छा रिजल्ट लाकर ना केवल साकार किया बल्कि शिक्षकों का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। उसके माता-पिता का सपना बेटी को कलेक्टर बनते हुए देखना है।

फीस भी देंगे रिटायर्ड प्रिंसिपल

शिवानी और स्कूल के रिजल्ट से खुश रिटायर्ड प्रिंसिपल आनंद साहू ने इस पर टॉपर छात्रा को 5 हजार रुपए देने और 12वी तक की पढ़ाई की फीस देने की घोषणा की थी। वे 5 हजार रुपए दे चुके हैं।

प्रतिभा सम्मान संपन्न, बैतूल की दो प्रतिभाएं हुई सम्मानित

बैतूल। राष्ट्रीय भर्तृहरि विक्रम भोज पुरस्कार समिति का प्रतिभा सम्मान आयोजित किया गया। जिसमें बैतूल की दो प्रतिमाएं हुई सम्मानित हैं। पवार समाज वरिष्ठ जन कल्याण मंच बैतूल के प्रवक्ता और सेवानिवृत्त प्राचार्य बाबूराव पवार द्वारा सेवाकाल में की गई विशिष्ट सेवाओं यथा- रक्तदान, राष्ट्रीय सेवा योजना के जिला कार्यक्रम अधिकारी, तथा सामाजिक सेवाओं के लिए सुखवाड़ा के स्व.नारायण पवार स्मृति पुरस्कार से सेवानिवृत्त कुलपति मानसिंह परमार और स्व.नारायण पवार की धर्मपत्नी श्रीमती जयश्री पवार के द्वारा प्रशस्ति पत्र तथा 5000 रुपये की राशि भेंट कर सम्मानित किया गया। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ की विश्व शांति सेना में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले, भारतीय थल सेना को उनके शान्ति सेना में दुर्गम स्थलों पर दी गई सेवाओं के लिए बैतूल के ही घुडन् पवार से हवलदार, 5000 रुपये की सम्मान राशि और प्रशस्ति पत्र से मानसिंह परमार सेवानिवृत्त कुलपति एवं अन्य अतिथियों द्वारा पुरस्कृत कर

सम्मानित किया गया। घुडन् पवार दक्षिण अफ्रीका के कांगो तथा रवांडा के जीवित ज्वालामुखी तथा कीबुलेक मिथेन गैस रिसाव क्षेत्र में शांति सेना के अंग रहे। सम्मानित दोनों प्रतिभाओं को सम्मानित होने पर शुभचिंतक, इष्ट मित्रों सहित सामाजिक बंधुओं ने बधाई दी है।

अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर बैतूल में खुलकर हुई चर्चा, विशेषज्ञों ने कहा- दबाव नहीं, संवाद जरूरी

विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे, अधिवक्ताओं व चिकित्सकों ने व्यक्त किए प्रेरक विचार

बैतूल। अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस पर बैतूल में एसआईएफ बैतूल संस्था द्वारा आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में पुरुष मानसिक स्वास्थ्य, न्यायिक संतुलन और सामाजिक संवेदना पर खुलकर बात हुई। विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे से लेकर वरिष्ठ अधिवक्ताओं और चिकित्सकों ने पुरुषों के भावनात्मक संघर्षों को समझने की जरूरत बताई। मंच से कानून के दुरुपयोग, तनाव, जिम्मेदारी और संवाद पर प्रेरक विचार व्यक्त किए गए। कार्यक्रम में पीड़ित पुरुषों ने अपने वास्तविक संघर्ष साझा कर समाज को संवेदनशील होने का संदेश दिया। कार्यक्रम का संचालन डॉ. संदीप गोहे ने किया। मुख्य अतिथि विधायक डॉ. योगेश पंडाग्रे ने पुरुष मानसिक स्वास्थ्य पर चल रही मुहिम की सराहना करते हुए कहा कि समाज में संतुलन और सकारात्मक दिशा बनाए रखने के लिए पुरुषों की भावनात्मक स्थिति को समझना बेहद जरूरी है। उन्होंने इस पहल को समय की आवश्यकता बताते हुए अभियान को निरंतर सहयोग देने की घोषणा की। विशिष्ट अतिथि अधिवक्ता अंशुल गर्ग ने न्यायिक सुधारों पर बोलते हुए कहा कि 498 ए सहित कई कानूनों में सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं और न्याय पुरुष या महिला किसी एक पक्ष का नहीं, बल्कि तथ्यों और प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ता मारोतीराव बारस्कर ने कहा कि कानून का उद्देश्य सुरक्षा है, गलत उपयोग नहीं, और समाज में समानता तभी संभव है जब अधिकारों का प्रयोग ईमानदारी और जिम्मेदारी से किया जाए। कार्यक्रम में शामिल पीड़ित पुरुषों ने अपने व्यक्तिगत संघर्षों और मानसिक स्वास्थ्य से

जुड़े अनुभव साझा किए। कार्यक्रम के अंत में डॉ. संदीप गोहे ने मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों और सभी प्रतिभागियों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि पुरुष मानसिक स्वास्थ्य, न्यायिक संतुलन और सामाजिक संवेदना को नई दिशा देने में यह कार्यक्रम एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ है और सभी की उपस्थिति ने इसे सार्थक बनाया।

पुरुष भी भावनात्मक दबावों से गुजरते हैं- वरिष्ठ अधिवक्ता और अध्यक्ष अधिवक्ता संघ आमला केशव राव चौकीकर ने कहा कि पुरुष भी भावनात्मक दबावों से गुजरते हैं पर समाज के डर से बोल नहीं पाते, जबकि बोलना और मदद मांगना परिपक्वता का प्रतीक है। डॉ. अरुण जयसिंहपूरे ने कहा कि जिस तरह महिलाए स्वास्थ्य को लेकर जागरूक हो रही हैं उसी तरह पुरुषों को भी अपनी शारीरिक और मानसिक सेहत के प्रति जागरूक होना चाहिए, क्योंकि तनाव को अनदेखा करना भविष्य में गंभीर जोखिम बन सकता है। उन्होंने इस अभियान को समाज को स्वस्थ दिशा देने वाली महत्वपूर्ण पहल बताया।

कानून तभी सार्थक जब उसका प्रयोग संयमित व निष्पक्ष रूप से किया जाए

अधिवक्ता राजेंद्र उपाध्याय ने कहा कि अधिकांश विवाद ईगो और पावर के गलत उपयोग से बढ़ते हैं और कानून तभी सार्थक है जब उसका प्रयोग संयमित व निष्पक्ष रूप से किया जाए। डॉ. संदीप बर्डे ने कहा कि पुरुष अक्सर अपनी भावनाओं को दबा लेते हैं जिससे मानसिक दबाव बढ़ता है, जबकि अपनी बात साझा करना कमजोरी नहीं बल्कि समझदारी है। कार्यक्रम का मंच संचालन पत्रकार गौरी बालापुरे ने किया। उन्होंने कहा कि पुरुषों को परामर्श, सहयोग और ऐसा सुरक्षित वातावरण मिलना चाहिए जहां वे अपनी बात खुलकर रख सकें, क्योंकि किसी भी अधिकार का गलत उपयोग समाज और परिवार दोनों को कमजोर करता है।

बैतूल में सर्दी का असर हुआ तेज, रात का पारा 9.7 डिग्री पहुंचा

बैतूल। जिले में अब धीरे-धीरे सर्दी असर दिखाने लगी है। पिछले 12 दिनों में न्यूनतम तापमान 11.5 डिग्री तक नीचे आया है। रविवार को न्यूनतम तापमान 9.7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 4 नवंबर को जिले का तापमान 21.2 डिग्री सेल्सियस

था, जो 16 नवंबर को घटकर 9.7 डिग्री सेल्सियस रह गया। इस तरह मात्र 12 दिनों में तापमान में लगभग 11.5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज की गई है। दरअसल उत्तरी हवाओं के सक्रिय होने से मौसम में ठंडक बढ़ी है। सुबह और देर शाम के समय तेज ठंड महसूस की जा रही है। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों तक उत्तरी हवाएं सक्रिय रहेंगी। इससे रात के तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। दिन में धूप निकलने के बावजूद हवा में ठंडक बनी रहेगी। इधर अचानक बढ़ी ठंड के कारण जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। जिला अस्पताल के चिकित्सकों के अनुसार ठंड बढने के साथ ही अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की संख्या 800 से बढक़र प्रतिदिन लगभग 1000 तक पहुंच गई है। इनमें अधिकांश मरीज सर्दी-खांसी और जुकाम से पीड़ित हैं।

सांसद खेल महोत्सव 2025 क्रिकेट लेदर बॉल चयन ट्रायल का आयोजन 18 नवंबर को

बैतूल। केन्द्रीय राज्य मंत्री एवं सांसद बैतूल-हरदा-हरसूद लोकसभा संसदीय क्षेत्र दुर्गादास उईके के मार्गदर्शन में जिले में सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन किया जा रहा है। जिला खेल और युवा कल्याण अधिकारी ने बताया खेल संस्कृति को बढावा देने, स्वदेशी एवं मुख्यधारा खेलों को प्रोत्साहित करने, युवाओं की सहभागिता बढ़ाने तथा फिट इंडिया आंदोलन का समर्थन करने के लिए सांसद खेल महोत्सव 2025 का आयोजन संसदीय क्षेत्रों में किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि सांसद खेल महोत्सव 2025 के अंतर्गत क्रिकेट लेदर बॉल चयन ट्रायल का आयोजन 18 नवंबर 2025 को प्रातः 9 बजे से स्थानीय लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम में जिला क्रिकेट संघ के माध्यम से किया जाएगा। क्रिकेट चयन ट्रायल में इच्छुक खिलाड़ी निर्धारित ड्रेस सफेद टी-शर्ट-शर्ट, सफेद लोअर-पेंट में सम्मिलित होंगे। खिलाड़ी निर्धारित समय पर स्वयं के व्यय पर प्रतिभागिता करेंगे। चयन ट्रायल में खिलाड़ी को स्वयं की खेल किट लाना होगा। उन्होंने बताया कि चयन ट्रायल से संबंधित अधिक जानकारी के लिए क्रिकेट कोच मोइज मंसूरी मोबाइल नंबर 7000662399 पर संपर्क कर सकते हैं।

किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री ने सौंपा ज्ञापन

बैतूल। किसानों की समस्याओं को लेकर पूर्व कैबिनेट मंत्री सुखदेव पांसे ने एसडीएम राजीव कहार को ज्ञापन सौंपा है। इसमें उन्होंने कृषि कार्यों में आ रही विभिन्न समस्याओं का उल्लेख किया है, जिससे फसल उत्पादन क्षमता सीधे तौर पर प्रभावित हो रही है। किसानों ने बताया कि उन्हें नियमित बिजली आपूर्ति न मिलने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। सिंचाई के लिए निर्धारित समय पर बिजली न मिलने से फसलें सूखने की कगार पर पहुंच रही हैं। इसके अतिरिक्त, अस्थायी बिजली कनेक्शन भी चार माह से कम अवधि का नहीं दिया जा रहा है, जबकि सिंचाई के लिए पानी केवल दो से तीन माह तक ही पर्याप्त रहता है। इससे अतिरिक्त अवधि का विद्युत बिल किसानों पर अनावश्यक आर्थिक बोझ डाल रहा है। किसानों ने यह भी आरोप लगाया कि विभाग द्वारा 3 एचपी (हॉर्स पावर) का कनेक्शन नहीं दिया जा रहा, बल्कि उन्हें 5 एचपी का कनेक्शन लेने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह आर्थिक रूप से कमजोर किसानों के लिए भारी साबित हो रहा है। क्षेत्र में दिनभर कई बार होने वाली बिजली कटौती और 10 घंटे लगातार बिजली न मिलने से भी सिंचाई कार्य बाधित हो रहे हैं। किसानों के अनुसार, मेंटेनेंस के नाम पर सप्ताह में दो से तीन बार बिजली बंद की जाती है, जिससे वे परेशान हैं।

उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में भरत कुसुम मोदी अतिथि भवन का भूमिपूजन सम्पन्न

चातुर्मास समापन के बाद मुनिश्री ससंघ का आज मानतुंग गिरी की ओर विहार

धार। दिगम्बर जैन समाज धार में विराजित उपाध्याय श्री विभंजन सागर जी मुनिराज के परम पावन सानिध्य में विधानाचार्य पंडित भरत शास्त्री के मार्गदर्शन में समाज श्रेष्ठी दानवीर भरत कुसुम मोदी इंदौर द्वारा दिगम्बर जैन धर्मशाला के नव निर्माण हेतु भूमि पूजन सम्पन्न हुआ । विशेष अतिथि संजय अर्चना पाटोदी भी उपस्थित थे। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर जी में पूज्य मुनिश्री के द्वारा धार में प्रथम बार बच्चों व युवकों में उपनयन संस्कार व दम्पत्ति सदस्यों में दाम्पत्य संस्कार प्रदान किए गए ।

चातुर्मास पूर्ण होने के बाद परम पूज्य मुनिश्री का धार नगर से मानतुंगगिरी तीर्थ के लिए विहार हुआ। पूज्य मुनिश्री आगे आहु पार्श्वनाथ के दर्शन करते हुए अनारद की

ओर प्रस्थान करेंगे, वहाँ से कागदीपुरा तीर्थ की ओर विहार करेंगे । चातुर्मास समापन की पूर्व संध्या पर 卐 क्या खोया क्या पाया卐 कार्यक्रम का आयोजन हुआ । समाज अध्यक्ष श्रेणिक गंगवाल व सभी समाजजनो ने पूज्य गुरुदेव का चातुर्मास में जो सानिध्य पाया धर्म आराधना की व अपने जीवन की महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए सभी ने यह भावना प्रकट की गुरुदेव का सानिध्य पुनः धार समाज को मिले यह आग्रह पूज्य मुनिश्री के चरणो में निवेदित किया। चातुर्मास सफ़ल बनाने में संघस्थ प्रगति दीदी का विशेष सहयोग रहा ।

इस अवसर पर समाज के सभी पदाधिकारियों का सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन संजय छाबड़ा ने किया। जानकारी मीडिया प्रभारी संजय गंगवाल ने दी ।

महिला उद्यमिता को नई उड़ान, महिलाओं को 'लखपति दीदी' बनाने की दिशा में बड़ा कदम

आजीविका मिशन एवं पशुपालन विभाग द्वारा 155 समूह सदस्यों को मिला कड़कनाथ व देशी रंगीन चूजों का लाभ

सीहोर (निप्र)। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा महिलाओं की आर्थिक सशक्तिकरण और ÷लखपति दीदी÷ बनाने के लक्ष्य को ध्यान मां रखते हुए सीहोर जिले में एक महत्वपूर्ण पहल शुरू की गई है। मिशन अंतर्गत गठित 110 महिला स्वङ्कसहायता समूह सदस्यों को पशुपालन विभाग के अभिसरण से 30 अक्टूबर एवं 5 नवम्बर को बैकयार्ड पोल्ट्री योजना के तहत कड़कनाथ एवं देशी रंगीन नस्ल के चूजे वितरित किए गए, जिससे महिलाओं को स्थायी आय का स्रोत मिलने की दिशा में बड़ा अवसर प्राप्त हुआ है। देशी मुर्गी उच्च प्रोटीन व कम वसा के कारण बाजार में अत्यधिक मांग रखती है, जिससे ग्रामीण महिलाओं की आय में कई गुना वृद्धि की संभावना है। साथ ही भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय उच्च सुरक्षा पशुरोग संस्थान भोपाल के सहयोग से 45 महिलाओं को कड़कनाथ चूजों की पूर्ण इकाई - उच्च गुणवत्ता का मुर्गी आहार, देखरेख सामग्री तथा आगामी तीन माह तक तकनीकी मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा। आजीविका मिशन के जिला परियोजना प्रबंधक ने बताया कि जिला पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी द्वारा महिलाओं को लखपति दीदी बनाने हेतु पोल्ट्री क्लस्टर विकसित करने के निर्देश दिए गए थे। उन्हीं के मार्गदर्शन में पशुपालन विभाग के साथ अभिसरण कर महिलाओं को कड़कनाथ इकाइयाँ उपलब्ध कराई गई हैं।

पशुपालन एवं डेयरी विकास विभाग के उप संचालक श्री राजेन्द्र गौतम ने बताया कि आजीविका मिशन के अभिसरण से पिछले दो वर्षों से बैकयार्ड पोल्ट्री योजना का क्रियान्वयन हो रहा है। इसके उत्कृष्ट परिणाम सामने आए हैं। महिलाएं संगठित होकर घरङ्कआधारित स्वरोजगार स्थापित कर रही हैं। पशुपालन सखियों के मार्गदर्शन, टीकाकरण व दवाइयों की उपलब्धता से मुर्गी पालन में मृत्यु दर काफी कम हुई है और उत्पादन बढ़ा है। इसी कड़ी में 300 समूह सदस्यों को आगामी तिमाही में मुर्गी इकाइयों का वितरण किया जाएगा। एक इकाई के सही संचालन से एक महिला प्रति वर्ष 1 से 1.5 लाख रुपये तक की आय अर्जित कर सकती है। इस पहल से लाभान्वित महिलाओं ने विश्वास जताया कि उन्हें मुर्गी पालन से नियमित आय मिलेगी, घर के नजदीक ही रोजगार उपलब्ध होगा, बच्चों की शिक्षा, स्वास्थ्य और घर की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम होंगी, समूह में जुड़कर सामूहिक सीखने और विपणन के अवसर बढ़ेंगे। आजीविका मिशन का लक्ष्य है कि आने वाले समय में प्रत्येक ग्राम पंचायत में 8 से 10 लखपति दीदी तैयार की जाएं, ताकि महिलाएं न केवल आर्थिक रूप से सशक्त हों, बल्कि गांवों में स्थानीय भूमिका मॉडल भी बनें। इस योजना से न सिर्फ आजीविका के नए अवसर सृजित हो रहे हैं, बल्कि ग्रामीण महिलाएँ आत्मनिर्भरता, उद्यमिता और नेतृत्व की दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रही हैं। कड़कनाथ आधारित पोल्ट्री क्लस्टर जिले में महिला उद्यमिता और ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण साबित होगा।

बच्चों को कानूनी अधिकारों और गुड टच - बैड टच के बारे में किया गया जागरूक

सीहोर (निप्र)। प्रधान जिला न्यायाधीश श्री प्रकाश चंद्र आर्य के निर्देशानुसार न्यायोत्सव विधिक सेवा सप्ताह के अंतर्गत विद्यार्थीगण में कानूनी अधिकारों की समझ बढ़ाने के उद्देश्य से जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा शासकीय माध्यमिक शाला जमोनिया टैंक में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। कार्यक्रम में जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री जीशान खान द्वारा विद्यार्थियों को शिक्षकों के सम्मान, परिश्रम कर शिक्षा प्राप्त करने, गुड टच, बैड टच, किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ नहीं जाने एवं कोई सामान नहीं लेने, अपने भविष्य को संवारने आदि के बारे में जागरूक किया गया और विस्तार से जानकारी दी गई। इस दौरान बच्चो के लिये प्रतियोगिताओ का आयोजन भी किया गया जिसमें कुर्सी रेस, चम्मच रेस, गायन प्रस्तुतियां, व्यंजन निर्माण आदि गतिविधियां आयोजित की गईं। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा व्यंजनों के स्टॉल भी लगाये गए।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा छात्राओं व आम नागरिकों को किया गया जागरूक

विदिशा (निप्र)। वरिष्ठ कार्यालय खाद्य एवं औषधि प्रशासन भोपाल संभाग द्वारा संचालित चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला का भ्रमण शुक्रवार को विदिशा में किया गया। इस दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी विदिशा एवं केमिस्ट द्वारा शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के बालिका छात्रावास की छात्राओं को खाद्य पदार्थों की आसान जाँच एवं मिलावट पहचानने के व्यावहारिक तरीके बताए गए। केमिस्ट श्री अभिषेक तिवारी ने मौके पर विभिन्न खाद्य सामग्रियों की प्राथमिक जाँच प्रक्रिया समझाई।

संक्षिप्त समाचार

मेहलुआ चौराहा स्थित मेडिकल स्टोर्स पर की गई औषधि निरीक्षण कार्यवाही

विदिशा (निप्र)। अनुविभागीय अधिकारी कुरवाई के निर्देशन में आज तहसील कुरवाई के मेहलुआ चौराहा क्षेत्र में औषधि निरीक्षण की कार्यवाही की गई। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर द्वारा पाँच मेडिकल स्टोर्स की जांच की गई। निरीक्षण के दौरान औषधियों के भंडारण, लाइसेंस, बिलिंग एवं रजिस्टर संधारण संबंधी दस्तावेजों की जाँच की गई। जाँच के पश्चात संबंधित मेडिकल संचालकों को आवश्यक निर्देश प्रदान किए गए तथा नियमों का पालन सुनिश्चित करने हेतु सचेत किया गया।

ग्राम नटेरन में जलप्रदाय व्यवस्था का निरीक्षण, 22 मोटर पंप जब्त

विदिशा (निप्र)। मध्य प्रदेश जल निगम की सगड़ हिनोतिया माली समूह जलप्रदाय योजना के अंतर्गत निर्मित उच्च स्तरीय टंकी से संचालित पेयजल व्यवस्था का आज निरीक्षण किया गया। निरीक्षण कार्य में मध्यप्रदेश जल निगम की संचालन एवं संधारण टीम, ग्राम पंचायत नटेरन के सरपंच तथा पुलिस थाना नटेरन के आरक्षक उपस्थित रहे। निरीक्षण के दौरान जल जीवन मिशन की गाइडलाइन अनुसार नल कनेक्शन धारकों द्वारा जल आपूर्ति लाइन से अवैध रूप से मोटर पंप के माध्यम से जल उपयोग की जांच की गई। कार्रवाई के दौरान कुल 22 मोटर पंप जब्त किए गए, जिन्हें पुलिस थाना नटेरन में जमा कराया गया है।यह कार्रवाई पेयजल के समुचित वितरण एवं सभी उपभोक्ताओं को समान रूप से जल आपूर्ति सुनिश्चित करने के उद्देश्य से की गई है।

भावांतर योजना से किसानों के खेतों में खुशहाली छा रही - किसान श्री अतुल मीणा

विदिशा (निप्र)। विदिशा जिले के सोयाबीन उत्पादन करने वाले किसानों के खेतों में खुशहाली की लहर छा रही है और यह सब संभव हो पाया ये कहना है विदिशा जिले के ग्राम रिनिया के किसान श्री अतुल मीणा का। वे कहते हैं कि इस वर्ष उन्होंने अपनी 5 बीघा जमीन में सोयाबीन की फसल बोवनी की थी। भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित दर पर सोयाबीन विक्रय होने व भाव के अंतर को प्रदेश सरकार द्वारा पूरा करने से उन्हें मुनाफा होगा। रिनिया गांव के किसान श्री अतुल मीणा ने कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखंड नटेरन में बताया कि उन्होंने अपनी 10.44 क्विंटल सोयाबीन बैरसिया की नवीन कृषि उपज मंडी में तुलवाई थी। आज उनके बैंक खाते में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत राशि प्राप्त हुई, जिससे वह बेहद खुश हैं। उन्होंने कहा है की भावांतर भुगतान योजना किसान हित में मध्य प्रदेश सरकार का एक बड़ा कदम है। इस योजना से पूरे प्रदेश के किसान लाभान्वित हो रहे हैं, उन्होंने इस योजना के लिए प्रदेश सरकार और मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त किया है।

न्यायोत्सव के तहत विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन

विदिशा (निप्र)। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के दिशा-निर्देशों एवं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री शेख सलीम के मार्गदर्शन में न्यायोत्सव दृ विधिक जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार, 13 नवम्बर को जिला न्यायाधीश श्रीमति सुरेखा मिश्रा, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विदिशा श्री नितेन्द्र सिंह तोमर, प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट श्रीमति शिवांगी श्रीवास्तव एवं लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्री अनिमेष तिवारी द्वारा बालिका संप्रेक्षण गृह, शिशुगृह एवं दीक्षा निकेतन विशेष विद्यालय में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। शिविर के दौरान जिला न्यायाधीश श्रीमति सुरेखा मिश्रा ने बालिका संप्रेक्षण गृह की अधीक्षक श्रीमति आकांक्षा मरावी को निर्देश दिए कि बालिकाओं को पढ़ाई के साथ-साथ चित्रकला जैसी विभिन्न कलाओं का प्रशिक्षण दिया जाए ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। अधीक्षक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में संप्रेक्षण गृह में 03 बालिकाएँ निवासरत हैं। प्रिंसीपल मजिस्ट्रेट श्रीमति शिवांगी श्रीवास्तव ने दीक्षा निकेतन विशेष विद्यालय में उपस्थित बच्चों को अच्छे एवं बुरे स्पर्श की जानकारी देकर उन्हें आत्म-सुरक्षा के प्रति जागरूक किया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव श्री नितेन्द्र सिंह तोमर ने बच्चों को मुफ्त विधिक सहायता की व्यवस्था और नालसा के टोल फ्री नंबर 15100 की जानकारी दी तथा बताया कि किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

नरवाई प्रबंधन की पहल में कृषकों की भागीदारी जारी

विदिशा (निप्र)। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री अंशुल गुप्ता के मार्ग दर्शन में नरवाई प्रबंधन को लेकर चलाई जा रही विशेष मुहिम को निरंतर सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं। इसी क्रम में आज शुक्रवार को विकासखंड नटेरन के ग्राम नेवली एवं फूफेर (बलरामपुर) में रोटावेटर के माध्यम से धान की पराली को खेत में ही मिलाकर खाद के रूप में उपयोग करने का सफल प्रयोग किया गया। ग्राम नेवली निवासी किसान श्री बहादुर सिंह दांगी ने अपने खेत में इस तकनीक को अपनाकर न केवल पराली जलाने से होने वाले प्रदूषण को रोका, बल्कि भूसे को कम्पोस्ट खाद के रूप में उपयोग करके मिट्टी की उर्वरकता बढ़ाने की दिशा में सराहनीय पहल की है। यह प्रयोग नरवाई प्रबंधन के क्षेत्र में एक सफलतम मॉडल के रूप में उभर रहा है।

प्रेरणा

शिविरों एवं कार्यशालाओं से मिली प्रेरणा नरवाई प्रबंधन जागरूकता अभियान तथा विकसित कृषि संकल्प अभियान के तहत आयोजित ग्राम स्तरीय शिविरों और कार्यशालाओं ने किसानों को नई तकनीकों से अवगत कराया है। क्षेत्रीय कृषि अधिकारी श्री अभिषेक जैन एवं आत्मा परियोजना से श्री अनिकेत रघुवंशी द्वारा समय-समय पर दी गई कृषिगत जानकारियों से किसानों को महत्वपूर्ण लाभ मिला। विशेषकर नरवाई प्रबंधन हेतु भूसा एकत्रीकरण,उन्नत कृषि यंत्रों की जानकारी,प्राकृतिक खेती उन्मुखीकरण, प्रचार-प्रसार कार्यक्रम जैसी गतिविधियों ने किसानों में जागरूकता और आत्मविश्वास बढ़ाया है।

भागीदारी

जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों की सक्रिय भागीदारी मिल रही है।ग्राम पंचायत फूफेर के सरपंच प्रतिनिधि श्री तेजप्रताप सिंह राजपूत एवं किसान श्री बहादुर सिंह दांगी द्वारा कृषि विभाग के सहयोग से समय-समय पर पंचायत स्तर पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इनमें प्रमुख रूप से बीज उपचार महाअभियान,नरवाई प्रबंधन जागरूकता कार्यक्रम, कृषक संगोष्ठी,बीज वितरण, उन्नत कृषि यंत्रों के उपयोग संबंधी प्रशिक्षण जैसी गतिविधियाँ शामिल हैं। इन कार्यक्रमों से ग्रामीण किसानों में नवाचार अपनाने की प्रवृत्ति तेजी से बढ़ रही है।

बाईक रैली के साथ किया विधिक सेवा सप्ताह का समापन

बैतूल (निप्र)। मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार जिले में न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह 9 नवम्बर से 14 नवम्बर 2025 तक मनाया गया। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल की उपस्थिति में विधिक सेवा सप्ताह का समापन शुक्रवार को बाईक रैली के साथ किया गया। बाईक रैली को प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बैतूल श्री थपलियाल द्वारा हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। उक्त रैली न्यायालय परिसर बैतूल से बस स्टेड रोड होते हुए अंबेडकर चौक से मैकनिक चौक , बाबू चौक होते हुए कॉलेज रोड से गणेश चौक, कोठीबाजार से कोतवाली थाना, लक्ष्मी चौक होते हुए वापस जिला न्यायालय परिसर बैतूल में पहुंची, जहां रैली का समापन किया गया। समापन अवसर पर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश / अध्यक्ष महोदय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बैतूल श्री दिनेश चन्द्र थपलियाल द्वारा समस्त प्रतिभागियों को संबोधित करते हुये 07 दिवसीय न्यायोत्सव कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी दी। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण- श्रीमती शर्मिला बिलवार द्वारा आभार व्यक्त किया गया। इसके अलावा सीएम साईज स्कूल बैतूल बाजार बैतूल में निबंध, चित्रकला एवं क्विज प्रतियोगिता कराई गई एवं श्री विद्या मंदिर स्कूल हमलापुर बैतूल में नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया। बाईक रैली एवं 07 दिवसीय न्यायोत्सवः विधिक सेवा सप्ताह का उद्देश्य विधिक सेवा योजनाओं के प्रचार-प्रसार एवं उक्त योजनाओं का लाभ लेने के संबंध में विहित प्रक्रिया की जानकारी तथा जनसामान्य तक न्याय की पहुंच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से साप्ताहिक जागरूकता, साक्षरता कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की गई।

बाईक रैली में जिला न्यायाधीश श्री सचिन कुमार घोष, श्री कैलाश नारायण अहिरवार, डॉ. कु.महजबीन खान, श्रीमती ज्ञानेश्वरी कुमरे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्रीमती संगीता भारती राठौर, सचिव श्रीमती शर्मिला बिलवार, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड श्री सुरेश यादव, जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री सोमनाथ राय, श्री बी.के. पांडे, श्री संजय शुक्ला, श्री अवध हजारे अन्य न्यायाधीशगण, न्यायालयीन कर्मचारी, अधिवक्तागण, पुलिस विभाग, लीगल एड डिफेंस काउंसल, पैरालीगल वॉलेंटियर्स तथा एनजीओं के सदस्य व कार्यकर्ता तथा विधि महाविद्यालय के छात्र, एनएसएस/एनसीसी/स्पोर्ट में संबंधित विद्यार्थियों ने भाग लिया।

125 दिवसीय सिकल सेल एनीमिया अभियान का उत्कृष्ट क्रियान्वयन, मुख्यमंत्री डॉ यादव करेंगे सम्मानित

बैतूल (निप्र)। बैतूल जिले ने 125 दिवसीय सिकल सेल एनीमिया स्क्रीनिंग और जागरूकता अभियान में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती पर जबलपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मनोज हुरमाड़े और नोडल अधिकारी डॉ. अंकिता सीते को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। सीएमएचओ डा.मनोज हुरमाडे ने बताया की जनजातीय बहुल बैतूल जिले में सिकल सेल नियंत्रण के लिए कलेक्टर श्री नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी और जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री अक्षत के मार्गदर्शन में ÷सिकल मित्र ÷नामक नवाचार शुरू किया गया। इस पहल के तहत युवाओं, शिक्षकों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और विद्यार्थियों को विशेष प्रशिक्षण देकर सिकल सेल रोग की पहचान, स्क्रीनिंग प्रक्रिया, जेनेटिक काउंसलिंग और प्रारंभिक परामर्श की जानकारी दी गई। अभियान के दौरान स्कूलों और महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम, पोस्टर प्रतियोगिताएँ, रैलियाँ और शिविर आयोजित किए गए, जबकि डिजिटल माध्यमों – सोशल मीडिया, व्हॉट्सऐप और रेडियो के जरिए समुदाय तक महत्वपूर्ण जानकारी लगातार पहुंचाई गई। सिकल मित्रों ने स्वास्थ्य विभाग के शिविरों में सक्रिय भूमिका निभाते हुए ग्रामीणों को परीक्षण केंद्रों से जोड़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

इन प्रयासों का परिणाम यह रहा कि केवल 100 दिनों में 1.80 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की गई और 107 सिकल मित्र प्रशिक्षित कर मैदान में उतारे गए। जागरूकता बढ़ने के साथ विवाह पूर्व जाँच और परामर्श की प्रवृत्ति में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई। सिकल सेल उन्मूलन अभियान के तहत अब तक जिले में 11 लाख से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग की जा चुकी है , जिसमें 1456 सिकल सेल एनीमिया रोगी और 6502 वाहक चिन्हित किए गए हैं। लगातार जारी इस सामूहिक प्रयास ने बैतूल को सिकल सेल नियंत्रण के क्षेत्र में प्रदेश के अग्रणी जिलों में स्थापित कर दिया है।

सीएम डेयरी प्लस योजना के तहत पशुपालकों को मुर्रा नस्ल की दो-दो भैंसे प्रदान की गई

विदिशा (निप्र)। पशुपालन विभाग द्वारा संचालित सीएम डेयरी प्लस योजना के तहत जिले के 10 हितग्राहियों को अनुदान पर दो-दो मुर्रा नस्ल की भैसे प्रदान करने के लिए चयन कर हितग्राहियों की अंशदान राशि 50 प्रतिशत डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से पशुधन विकास निगम मे हितग्राहियों की सूची सहित जमा करा दी गई है। जिन्हें अतिशीघ्र हरियाणा ले जाकर हितग्राहियों के पसन्द अनुसार भैस क्रय कराई जाएगी। विदित हो, कि सीएम की मंशानुसार प्रदेश में दुग्ध उत्पादन आगामी 5 वर्षो में 9.00 लाख लीटर प्रतिदिन से 20.00 लाख लीटर प्रतिदिन करना है। इसके लिए दुग्ध समृद्धि संपर्क अभियान, क्षीर धारा ग्राम योजना, राष्ट्रीय कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम अभियान संचालित किए जा रहे हैं।

रायसेन में भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत जिला स्तरीय कार्यक्रम सम्पन्न

रायसेन (निप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव द्वारा देवास में आयोजित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में प्रदेश के 1.33 लाख किसानों को 233 करोड़ रूपए की भावान्तर राशि का अंतरण किया गया। रायसेन स्थित वन परिसर में आयोजित भावांतर योजन राशि अंतरण के जिला स्तरीय कार्यक्रम का जिला पंचायत अध्यक्ष श्री यशवंत मीणा, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता सेन तथा अपर कलेक्टर श्री मनोज उपाध्याय द्वारा दीप प्रज्जवलन कर शुभारंभ किया गया। वन परिसर में मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के उद्बोधन का लाईव प्रसारण भी देखा व सुना गया। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष श्री मीणा ने उपस्थित किसानों तथा आमजन को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव द्वारा अनेक किसान किसान हितैषी योजनाएं संचालित की जा रही है। प्रदेश सरकार द्वारा सोयाबीन उत्पादक किसानों को उपज का उचित लाभ दिलवाने के लिए भावान्तर योजना लागू की है और आज किसानों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से राशि अंतरित की गई है। उन्होंने बताया कि जिले में 24 अक्टूबर से 06 नवम्बर तक सोयाबीन विक्रय करने वाले 1443 किसानों को कुल दो करोड़ 95 लाख 54 हजार 947 रू की राशि वितरित की गई है। इसमें रायसेन तहसील के 107 किसानों के खाते में 20 लाख 49 हजार 941 रू की राशि अंतरित की गई है। कार्यक्रम में नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सविता सेन तथा श्री राकेश शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर रायसेन एसडीएम श्री मनीष शर्मा ने जानकारी दी कि भावांतर भुगतान योजना में 01 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 2025 तक रायसेन जिले के कुल 9051 किसानों द्वारा 26215 हैक्टेयर रकबा पंजीकृत कराया गया है जिसमें से रायसेन तहसील के 1318 किसान पंजीकृत हैं। भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत 24 अक्टूबर से 12 नवम्बर तक जिले में 2562 किसानों द्वारा 51766 क्विंटल सोयाबीन का विक्रय किया जा चुका है जिसमें रायसेन तहसील के 159 किसानों द्वारा 2650 क्विंटन सोयाबीन का विक्रय किया गया है।

विशेष गहन पुनरीक्षण के सम्बन्ध में राजनैतिक दलों को दी गई जानकारी

राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित

बैतूल (निप्र)। प्रभारी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अक्षत जैन की अध्यक्षता में शुक्रवार को कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण-2026 के संबंध में राजनीतिक दलों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने जिले में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण की आवश्यक जानकारी दी और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की जिज्ञासाओं का समाधान किया। उन्होंने बताया कि जिले में मतदाता की मैपिंग का कार्य 77.58 प्रतिशत पूर्ण हो चुका है, जिसमें जिला प्रदेश में अव्वल है। बीएलओ पुन-घर-घर जाएंगे और मतदाताओं से भरा हुआ फार्म प्राप्त करेंगे। यदि मतदाता अपनी जानकारी भरने में असमर्थ है, तो बीएलओ गणना पत्रक भरने में उनका सहयोग करेंगे। उन्होंने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण 2003 की मतदाता सूची की जानकारी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट voters.eci.gov.lnया मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय मप्र की वेबसाइट ceo-election.mp.gov.in से प्राप्त कर सकेंगे। वहीं बीएलओ सीधे मतदाता को बता पाएंगे कि आपका मिलान 2003 की एसआईआर सूची में है, जिससे उन्हें गणना पत्रक भरने में परेशानी नहीं आएगी। इसके अलावा महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले मतदाता एसआईआर का डाटा https://ceoelection.maharashtra.gov.in/w®®w/w®®wroll-data.asp& पर देख सकेंगे। बीएलए की जानकारी उपलब्ध कराने के दिए निर्देश बैठक में कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि कार्यक्रम में समस्त राजनैतिक दलों की भागीदारी भी सुनिश्चित की गई है। उन्होंने राजनीतिक दलों से शेष रह गए अपने-अपने बीएलए की जानकारी जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराए जाने के निर्देश दिए, ताकि उन्हें शीघ्र प्रशिक्षण दिया जा सके। कलेक्टर श्री जैन ने कहा कि निर्धारित कार्यक्रम के तहत बीएलओ नए मतदाता के नाम को जोड़ने के लिए फार्म-6, नाम विलोपन के लिए फॉर्म-7 और नाम संशोधन के लिए फार्म -8 भरकर एकत्र करेंगे।

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री जैन ने बताया कि एसआईआर में विशेष बात यह है कि मतदाता को गणना प्रपत्र के साथ किसी अन्य दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी। सभी ईआरओ और एईआरओ बीएलओ से प्राप्त गणना प्रपत्र के आधार पर ही मतदाताओं का नाम प्रारूप सूची में शामिल करेंगे।

जिन मतदाताओं के नाम का पिछले एसआईआर से मिलान नहीं होगा, उन्हें निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नोटिस जारी किया जाएगा। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी द्वारा ऐसे मामलों की सुनवाई कर पात्रता निर्धारित करते हुए उनके नामों को अंतिम नामावली में शामिल करने या हटाने का निर्णय लिया जाएगा।

पं. धीरेंद्र शास्त्री की पदयात्रा के साथी बने सीएम मोहन

● सड़कों पर पैदल चले मुख्यमंत्री, हाईवे पर बैठकर भोजन किया ● पदयात्रा का बांके बिहारी मंदिर पर हुआ समापन

भोपाल/ मथुरा (नप्र)। पंडित धीरेंद्र शास्त्री की सनातन हिंदू एकता पदयात्रा 2.0 का रविवार को समापन हो रहा है। इसमें शामिल होने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव भी मथुरा पहुंचे हैं। वे धीरेंद्र शास्त्री के साथ पैदल चले। सीएम ने दिल्ली-आगरा नेशनल हाईवे पर बैठकर बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर के साथ भोजन भी किया। पदयात्रा आज ही वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर पर समाप्त होगी। इससे पहले चार धाम के पास सनातन सभा होगी। इसके लिए 15 एकड़ ग्राउंड में पदयात्रियों के बैठने की व्यवस्था की गई है। एक बड़ा सा मंच लगाया गया है, जहां से संत पदयात्रियों को संबोधित करेंगे।

सभा में पंडित धीरेंद्र शास्त्री के साथ जगद्गुरु रामभद्राचार्य, पुंडरीक महाराज, इंद्रेश उपाध्याय, देवकीनन्दन ठाकुर सहित बड़ी संख्या में संत महात्मा मंच पर मौजूद हैं। शास्त्री ने सभी संतों का आशीर्वाद लिया और पट्टिका पहनाकर उनका सम्मान किया।

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा- जो भी हिन्दू बनना चाहेगा उसे हिंदू बनाएंगे- जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा- हम चाहते हैं समान नागरिक संहिता लाई जाए। इनके यहां भेड़ों की तरह 25-25 बच्चे पैदा हो जाएं। उन्होंने कहा- सारे हिन्दुओं को जागरूक होना होगा।

हम परावर्तन सिद्धांत अपनाएंगे। जो भी हिन्दू बनना चाहेगा उसे हिंदू बनाएंगे और उनकी सुरक्षा करेंगे।

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा- बहुत दिनों ओम शांति किया अब ओम क्रांति होगा- जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने कहा-शीघ्र दिल्ली से कश्मीर तक हिन्दू एकता पदयात्रा निकालेंगे। मैं पूरा समय दूंगा। अब तक हम सो रहे थे तो विधर्मी हमारा अपमान कर रहे थे लेकिन अब हिन्दू जग गया है। बहुत दिनों हम लोगों ने ओम शांति किया लेकिन अब ओम क्रांति ओम क्रांति कर रहे हैं।

आचार्य रामचंद्र दास बोले-अयोध्या बदली, काशी बदली, अब मथुरा की बारी है- जगद्गुरु रामभद्राचार्य के शिष्य आचार्य रामचंद्र दास ने कहा- हमने बदली अयोध्या, बदली काशी, अब मथुरा की बारी है। राम खड़े हैं धनुष लिए, अब बंशी बजने वाली है।

जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य ने धीरेंद्र शास्त्री को गले लगाया- धीरेंद्र शास्त्री ने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य को पट्टिका पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान जगद्गुरु ने उन्हें गले से लगा लिया। और सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। वहीं गंगा-यमुना की आरती के बाद सभी संतों को धीरेंद्र शास्त्री ने पट्टिका पहनाकर स्वागत किया।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने

जबलपुर के सूर्या हॉफ मैराथन-2025 में नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़कर दी बधाई

भोपाल (नप्र)। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने रविवार को जबलपुर में सूर्या हॉफ मैराथन-2025 के तृतीय संस्करण की नई दिल्ली से वर्चुअली जुड़ कर आयोजन के लिए बधाई और शुभकामनाएं दीं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इस अवसर पर जबलपुर में विद्यमान मध्य भारत एरिया के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेन्ट जनरल श्री पदम सिंह शेखावत और सूर्या हॉफ मैराथन के आयोजन से जुड़ी सेना की टीम और धावकों से वर्चुअली संवाद किया।

लेफ्टिनेन्ट जनरल श्री पी.एस. शेखावत ने बताया कि यह मैराथन जबलपुर को भारत के खेल मानचित्र पर उभारने के उद्देश्य से आयोजित की जा रही है। समाज के सभी वर्गों, मुख्यत- युवा वर्ग में खेल कूद और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाना, जबलपुर को पर्यटन केन्द्र के रूप में बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना भी मैराथन का उद्देश्य है।

मैराथन से होने वाली आय का एक भाग दृष्टि बाधित केन्द्र के उत्थान को समर्पित किया जाएगा। इस मैराथन को क्रमश- 21, 10, 05 और 03 किलोमीटर श्रेणी में आयोजित किया गया। इसमें मध्यप्रदेश के अलावा अन्य राज्यों से भी विभिन्न आयु वर्गों के लगभग 10 हजार धावकों ने भाग लिया।

शहडोल में बाघ का शिकार करंट लगने से हुई मौत

वन विभाग ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार, खेत में अंगो को दबाया था

शहडोल (नप्र)। शहडोल के ब्यौहारी वन क्षेत्र में करंट की चपेट में आने से एक बाघ की मौत हो गई। शिकारियों ने बाघ के अंगों को एक स्थान पर दफना दिया था। इस मामले में वन विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

खूटियों का उपयोग कर करंट लगाया था।

अंगों को बोचरो क्षेत्र में दबाने के बाद फरार हो गए थे आरोपी- वन विभाग के क्षेत्र अधिकारी अर्पित मैराल ने इस घटना को एक गंभीर अपराध बताया। उन्होंने कहा कि आरोपी

खेत में बाघ के अंग मिले- यह मामला तब सामने आया जब राजस्व ग्राम बोचरो के एक खेत में बाघ के अंग मिले। किसानों ने खेत में बाघ के अंग देखकर वन विभाग को सूचित किया। इसके बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और संबंधित अंगों का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ वन अपराध दर्ज किया गया था।

पुलिस ने दो आरोपियों को किया गिरफ्तार- वन विभाग और एस.टी.एस.एफ. जबलपुर की एक संयुक्त टीम ने विस्तृत जांच की। जांच के बाद ग्राम बोचरो के स्थानीय निवासी अम्ब्रीश लोनी और लल्लू कोल को गिरफ्तार किया गया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने जंगली जानवरों का शिकार करने के लिए तार और घटना के बाद बाघ के शव के टुकड़े करके कुछ अंगों को बोचरो क्षेत्र में दबाने के बाद फरार हो गए थे। म.प्र. पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी ब्यौहारी के कनिष्ठ अभियंता ने भी इस घटना की पुष्टि की है।

अधिकारी बोले-मामले की कर रहे हैं जांच - आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद, उन्हें घटनास्थल पर ले जाकर मौके का निरीक्षण कराया गया। जांच में पाया गया कि आरोपियों ने बाघ के कुछ अंगों को चीटीमार तालाब में भी दबा दिया था। वन विभाग की टीम ने तालाब से उन अंगों के साथ-साथ शेष संबंधित सामान भी जब्त कर लिया। आरोपियों को न्यायालय ब्यौहारी में पेश किया गया, जहाँ से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। मामले की जांच अभी जारी है।

ट्रैक्टर-ट्रॉली में घुसी फॉर्च्यूनर, 5 की मौत

ग्वालियर में गाड़ी काटकर निकालने पड़े शव, मृतकों में एक प्रॉपर्टी कारोबारी का इकलौता बेटा

ग्वालियर (नप्र)। ग्वालियर में तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार रेत से भरे ट्रैक्टर-ट्रॉली से जा टकराई। टक्कर इतनी

जबरदस्त थी कि फॉर्च्यूनर सवार सभी पांच लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। कार ट्रॉली के नीचे घुस गई, जिसकी वजह से कोई भी यात्री बच नहीं पाया।

हादसा ग्वालियर-झांसी हाइवे पर शहर से करीब 20 किलोमीटर पहले रविवार सुबह साढ़े 5 से 6 बजे के बीच हुआ। सभी मृतक ग्वालियर निवासी बताए जा रहे हैं। वे फॉर्च्यूनर में उत्तर प्रदेश के झांसी से एक कार्यक्रम में शामिल होकर ग्वालियर लौट रहे थे। कार जैसे ही मालवा कॉलेज के सामने पहुंची, मोड़ पर रेत से भरी ट्रैक्टर-ट्रॉली सामने आ गई। तेज रफ्तार होने के कारण ड्राइवर, कार को नियंत्रित नहीं कर सका और कार पीछे से ट्रॉली में घुस गई।

शव कार और ट्रॉली के बीच बुरी तरह फंसे हुए थे। पुलिस और स्थानीय निवासियों ने कटर मशीन की मदद से गाड़ी को काटकर शवों को बाहर निकाला।

प्रॉपर्टी कारोबारी का इकलौता बेटा था प्रिंस

फॉर्च्यूनर ग्वालियर के प्रॉपर्टी कारोबारी उमेश राजावत की है। शनिवार रात करीब 9 बजे वे शनिचरा धाम से लौटे थे। उसके इकलौता बेटा प्रिंस राजावत कार ले गया था। नेशनल हाईवे एम्बुलेंस के प्रायमरी मेडिकल ऑफिसर पंकज यादव ने बताया कि सुबह करीब साढ़े 6 बजे सिरोल थाने से सूचना मिली थी कि मालवा कॉलेज के सामने हादसा हुआ है। वे डबरा से टीम सहित सुबह 7-00 बजे मौके पर पहुंचे। मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि फॉर्च्यूनर की रफ्तार करीब 160 किमी प्रतिघंटा थी। पुलिस ने कार के दरवाजे तोड़कर घायलों को बाहर निकाला।

कार के एयरबैग खुलकर फटे

पुलिस के मुताबिक, कार के एयरबैग खुलकर फट गए हैं। इससे अंदाजा लगाया जा रहा कि कार की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास होगी।प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि कार से शराब की खाली बोतल और खाली डिस्पोजेबल गिलास भी मिले हैं।सीएसपी नागेंद्र सिंह सिकरवार ने बताया कि हादसे के कारणों की जानकारी जुटा रहे हैं।

'लॉरेंस बिश्नोई विदेशों में आतंकी घोषित, भारत में क्यों नहीं'

क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बोले- वह धर्मयोद्धा नहीं, देश को नुकसान पहुंचाने वाला अपराधी है

भोपाल (नप्र)। क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग को लेकर कड़ा रुख दिखाया। उन्होंने साफ कहा कि लॉरेंस कोई धर्म योद्धा नहीं, बल्कि वह देश को नुकसान पहुंचाने वाला संगठित अपराधी है। वह विदेश में बैठकर गैंग चलाता है, नशे का व्यापार करता है, फिरौतियां वसूलता है और समाज के प्रभावशाली व्यक्तियों पर हमले करवाता है। उसकी गतिविधियां किसी भी मायने में आतंकवाद से कम नहीं हैं।

शेखावत ने केंद्र सरकार पर भी सवाल उठाते हुए कहा - सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि विदेशों में कई जगह इस गैंग को आतंकवादी घोषित किया गया, लेकिन भारत की सरकार अभी तक इसे आतंकवादी संगठन घोषित क्यों नहीं कर रही? देश का व्यापारी वर्ग भयभीत है। वही व्यापारी जो देश की आर्थिक रीढ़ है, उससे आज भी यह गैंग फिरौतियां मांग रहा है। व्यापारियों का डर देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है, पर सरकार की चुप्पी समझ से परे है। उन्होंने आगे कहा कि सुखदेव सिंह गोगामी की हत्या केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सामूहिक चोट है। ऐसे अपराधियों का इस देश में क्या दुनिया में होना भी दुख की बात है।

यदि मेरे मुखिया को इन्होंने मारा है, तो यह सिर्फ हमारा नुकसान नहीं, पूरा समाज इसकी पीड़ा महसूस करता है।

बता दें कि क्षत्रिय करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राज सिंह शेखावत ने लॉरेंस बिश्नोई का एनकाउंटर करने वाले पुलिसकर्मी को 1 करोड़ 11 लाख 11 हजार 111 रुपए का नकद पुरस्कार देने का ऐलान किया था। राज शेखावत ने गुजरात से वीडियो जारी कर यह घोषणा की।

एमपी में रिकॉर्ड ठंड...भोपाल-इंदौर में पारा 6.4 डिग्री

राजधानी में टूट सकता है 84 साल का रिकॉर्ड, कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट

भोपाल (नप्र)। पहाड़ों की बर्फबारी के असर से मध्यप्रदेश में नवंबर की सर्दी रिकॉर्ड तोड़ रही है। भोपाल में रात का पारा 0.3 डिग्री लुढ़कते ही 84 साल का रिकॉर्ड टूट जाएगा। रविवार की रात यहां पारा 6.4 डिग्री दर्ज किया गया। ओवरऑल रिकॉर्ड 30 नवंबर 1941 में 6.1 डिग्री का है। इंदौर में भी पारा 6.4 डिग्री ही रहा। यहां भी सीजन की सबसे सर्द रात रही। 25 साल में पहली बार पारा इतना लुढ़का है।

जबलपुर में भी इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। पहली बार पारा 8.5 डिग्री पर आया। उज्जैन में 10.5 डिग्री और ग्वालियर में 10.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इंदौर में एक ही रात में 3.2 डिग्री की गिरावट- बीती रात प्रदेश के सभी शहरों में पारे में खासी गिरावट हुई। शुक्रवार-शनिवार की रात इंदौर में पारा 9.6 डिग्री रहा था, जो बीती रात 6.4 डिग्री पर आ गया। यानी, एक ही रात में पारा 3.2 डिग्री लुढ़क गया। भोपाल-धार में 1.6 डिग्री, नर्मदापुरम, जबलपुर, मंडला-उज्जैन में 1.2 डिग्री, सिवनी में 1 डिग्री, उमरिया में 1.1 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई।

राजगढ़ में पारा 6 डिग्री पर पहुंचा- राजगढ़ में 0.5 डिग्री की गिरावट के बाद पारा 6 डिग्री पर आ गया। राजगढ़ में सीजन में पहली बार तापमान इतना लुढ़का है। उमरिया में

7.3 डिग्री, रीवा में 7.4 डिग्री, छतरपुर के नौगांव में 7.6 डिग्री, मंडला-मलाजखंड में 8.8 डिग्री, शिवपुरी में 9 डिग्री, छिंदवाड़ा में 9.2 डिग्री, दमोह में 9.6 डिग्री और बैतूल में पारा 9.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

इस वजह से प्रदेश में तेज ठंड- पहाड़ी राज्य- उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बर्फबारी हो रही है। इसका असर एमपी में भी हो रहा है। उत्तरी हवाएं सीधे प्रदेश में आ रही हैं। इस वजह से रातें ठंडी है। दिन में धूप निकलने से ठंड का असर उतना नहीं रहता।

सीनियर मौसम वैज्ञानिक डॉ. दिव्या ई. सुरेंद्रन ने बताया, पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश के कई जिलों में अति शीतलहर और शीतलहर का असर है। अगले 3 दिन भी कोल्ड वेव का अलर्ट है। इसके बाद थोड़ी राहत मिल सकती है।

इन जिलों में शीतलहर का अलर्ट- मौसम विभाग ने रविवार को भोपाल, इंदौर, राजगढ़, शाजापुर, देवास, सीहोर, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, रीवा, मैहर, कटनी, उमरिया, शहडोल, जबलपुर, डिंडौरी और अनूपपुर में शीतलहर का अलर्ट है।

इससे पहले शनिवार को भोपाल में लगातार 8 दिन तक शीतलहर का असर देखा गया। सीहोर, इंदौर, शाजापुर, शहडोल, जबलपुर, छतरपुर, शिवपुरी, रीवा, राजगढ़ में भी कोल्ड वेव का असर रहा।

कही-सुनी

रवि भोई

(लेखक पत्रिका समवेत सृजन के प्रबंध संपादक और स्वतंत्र पत्रकार हैं।)

निवेशकों को लुभाने में जुटी साय सरकार

छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव साय की सरकार सत्ता में आने के बाद से ही राज्य में इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर फोकस करते हुए नई उद्योग नीति लांच की और राज्य में निवेश के लिए उद्योगपतियों से लगातार संपर्क में है। राज्य में निवेश के लिए देश के उद्योगपतियों को न्योता देने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने महानगरों में इन्वेस्टर्स मीट किया। खबर है कि साय सरकार के 22 महीने के कार्यकाल में साढ़े सात लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। चार दिन पहले अहमदाबाद में आयोजित इन्वेस्टर कनेक्ट कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के सामने गुजरात के कई बड़े उद्योगपतियों ने राज्य में निवेश की इच्छा जताई। कहते हैं मुख्यमंत्री के साथ एक ही बैठक में गुजराती कारोबारियों ने 33 हजार करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दे दिया। यह छत्तीसगढ़ के लिए शुभ संकेत हैं। राज्य में निवेश आएगा तो रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। राजस्व बढ़ेगा साथ ही दूसरे धंधों में भी चार-चाँद लगेगा। इससे छत्तीसगढ़ को पर लगेंगे।

कब रिलीव होंगे महासमुंद एसपी आशुतोष सिंह

2012 बैच के आईपीएस आशुतोष सिंह का सीबीआई में डेपुटेशन का आदेश निकले करीब तीन हफ्ते हो गए हैं, पर सरकार ने उन्हें अभी तक रिलीव नहीं किया है। आशुतोष सिंह अभी महासमुंद जिले के एसपी हैं। ऐसे में चर्चा होने लगी है कि आशुतोष सिंह कब रिलीव होंगे। खबर है कि आशुतोष सिंह की जगह महासमुंद एसपी बनने के लिए कई दावेदार पैदा हो गए हैं। कहते हैं सभी दावेदार अपने -अपने स्तर से लॉबिंग भी कर रहे हैं। इस कारण महासमुंद एसपी तय करने में विलंब हो रहा है। सुनने में आ रहा है कि सीधी भर्ती वाले आईपीएस के साथ प्रमोटी आईपीएस भी महासमुंद के एसपी बनने में लगे हैं। बताते हैं पहले महासमुंद एसपी के लिए तीन नाम चल रहे थे अब आधे दर्जन से ज्यादा आईपीएस दौड़ में शामिल हो गए हैं। अब देखते हैं महासमुंद जिले के एसपी की कमान किसे मिलती है और आईपीएस आशुतोष सिंह कब रिलीव होते हैं।

कब तक खाली रहेगा संचालक उद्यानिकी का पद

आईएफएस अधिकारी एस जगदीशन के संचालक उद्यानिकी के पद से हटे एक महीने से ज्यादा समय होने को है, पर अब तक सरकार ने संचालक उद्यानिकी के पद पर किसी की पदस्थापना नहीं की है। बताते हैं कि सरकार ने एस जगदीशन को संचालक उद्यानिकी के पद से अचानक हटा दिया, पर किसी की पोस्टिंग नहीं की। संचालक उद्यानिकी के पद पर अब तक अधिकांश समय आईएफएस अधिकारी ही रहे हैं, पर कई मौकों पर आई ए एस अफसर भी संचालक उद्यानिकी रहे हैं। आमतौर से विभागाध्यक्ष का पद इतने लंबे समय तक खाली नहीं रहता। मजेदार बात है कि किसी अधिकारी को संचालक उद्यानिकी का प्रभार भी नहीं सौंपा गया है। उद्यानिकी विभाग में फिलहाल कोई अपर संचालक भी नहीं है। अब चर्चा होने लगी है कि सरकार ने संचालक उद्यानिकी का पद किसके लिए रिक्त रखा है या फिर उद्यानिकी का कृषि विभाग में विलय कर दिया जाएगा।

पवन साय को पश्चिम बंगाल में जिम्मा

बिहार फतह के बाद अब भाजपा का टारगेट पश्चिम बंगाल है। पश्चिन बंगाल में अगले साल मार्च -अप्रैल में विधानसभा चुनाव प्रस्तावित है। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में टीएमसी की सरकार है और भाजपा मुख्य विपक्षी दल है। चर्चा है भाजपा ने इस बार पश्चिम बंगाल में सत्तासीन होने के लिए अभी से ताकत झोंकना शुरू कर दिया है। रणनीतिक तौर पर अलग-अलग राज्यों के नेताओं की ड्यूटी वहां लगाई जा रही है। बताते हैं कि छत्तीसगढ़ भाजपा के महामंत्री संगठन पवन साय को भी कुछ सीटों का जिम्मा दिया गया है और वहां पार्टी की जीत सुनिश्चित करने का लक्ष्य दिया गया है। 2023 के छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने और सत्ता के द्वार तक पहुंचाने में पवन साय की अहम भूमिका रही थी। माना जा रहा है कि उनके अनुभव और रणनीतिक कौशल को देखते हुए उन्हें पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारी दी गई। पवन साय छत्तीसगढ़ भी देखेंगे और पश्चिम बंगाल में अपना जादू दिखाने का काम करेंगे।

टाइम पास वाली अफसर

कहते हैं कि एक महिला आईएएस अफसर काम से ज्यादा टाइम पास में दिलचस्पी लेती हैं। ये महिला आईएएस एक विभाग की डायरेक्टर हैं। महिला आईएएस अफसर के रैवेये से विभागीय मंत्री और सचिव दोनों परेशान बताए जाते हैं। चर्चा है कि महिला अफसर फैसला लेने की जगह पोस्टमेन का काम करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखाती हैं। बताते हैं महिला अफसर अपने स्तर पर निर्णय ले सकने वाली फाइलें ऊपर भेज देती हैं। इससे विभाग का काम थम जाता है या धीमा पड़ जाता है। सुनने में आता है कि ये अफसर अपने हिस्से का बला ऊपर वालों पर डालकर मुक्त हो जाती हैं और कुछ लोगों को अपने कक्ष में बैठाकर बातें करने में मशगूल हो जाती हैं। बताते हैं कई बार उनके विभागीय सचिव और मंत्री उन्हें अपने कंधे में जिम्मेदारी उठाने की समझाइश दे चुके हैं, पर महिला अफसर हैं कि मानती ही नहीं।

नितिन नबीन के विधानसभा में छत्तीसगढ़ की अफसर

कहते हैं छत्तीसगढ़ भाजपा के प्रभारी नितिन नबीन बिहार के बांकीपुर विधानसभा से पांचवीं बार विजयी रहे। नितिन नबीन के नामांकन दाखिले के समय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय वहां गए थे, तो चुनाव प्रचार में छत्तीसगढ़ के आधे दर्जन मंत्री, कई निगम मंडल अध्यक्ष और यहां के भाजपा नेता वहां पहुंचे थे। नितिन नबीन की जीत के बाद उनके विधानसभा क्षेत्र में डेरा जमाये नेता अब ताल ठोंक रहे हैं और जीत पर गदगद हैं। चर्चा है कि नितिन नबीन के बांकीपुर विधानसभा में चुनाव आयोग की आब्जर्वर छत्तीसगढ़ की एक महिला आईएएस अफसर थीं । छत्तीसगढ़ के कई आईएएस अफसर बिहार चुनाव में आब्जर्वर बनकर अलग-अलग विधानसभा में तैनात थे।

तीन आईएएस जा सकते हैं केंद्र में

चर्चा है कि 2006 बैच के आईएएस अंकित आनंद, 2011 बैच के दीपक सोनी और 2015 बैच के हरीश एस केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले हैं। बताते हैं अंकित आनंद भारत सरकार में संयुक्त सचिव बनने के लिए आवेदन करेंगे। अंकित आनंद अभी राज्य सचिव आवास -पर्यावरण हैं। दीपक सोनी और हरीश एस भारत सरकार में संचालक स्तर के पद के आवेदन करेंगे। आवेदन के बाद इंपैनल होने के बाद ये अफसर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाएंगे। दीपक सोनी अभी बलौदाबाजार -भाटापारा और हरीश एस बस्तर कलेक्टर हैं।

देर आयद ,दुरुस्त आयद

देर से ही सही, शहीद वीरनारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम को सरकार ने छत्तीसगढ़ राज्य क्रिकेट संघ को सौंपकर अच्छा फैसला किया है। देश के बड़े स्टेडियम में शुमार नवा रायपुर के इस क्रिकेट स्टेडियम में गिने -चुने वन-डे और आईपीएल मैच के अलावा कोई आयोजन ही नहीं हो रहा था। स्टेडियम उजाड़ हो रहा था और हर मैच के पहले सुधार पर काफी व्यय करना पड़ता था। छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ के पास जाने से उम्मीद है कि मैचों की संख्या बढ़ेगी और छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी भी स्टेडियम का बेहतर उपयोग कर सकेंगे। इस स्टेडियम को छत्तीसगढ़ क्रिकेट संघ को सौंपने की मांग काफी पुरानी थी। इस मांग को विष्णुदेव साय की सरकार ने पूरी की।

निजी मेडिकल कालेज सीबीआई की राडार पर

कहते हैं छत्तीसगढ़ का एक और निजी मेडिकल कालेज सीबीआई की राडार पर है। इस मेडिकल कालेज में भी मेडिकल सीट के लिए फर्जी तरीके अपनाने की शिकायत है। छत्तीसगढ़ में 3 -4 प्रायवेट मेडिकल कालेज हैं, बाकी सभी सरकारी हैं। पिछले दिनों रावतपुरा मेडिकल कालेज में सीट का कोटा बढ़ाने के लिए घूस देने के आरोप में निरीक्षण टीम के सदस्यों के साथ एक डायरेक्टर भी गिरफ्तार हो गए थे।